Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-18, अंक-21 01-15 नवंबर, 2023 (पाक्षिक) ₹20

प्रधानमंत्री ने 'नमो भारत' रैपिडएक्स ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

'विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के पक्ष में जबरदस्त उत्साह'

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 21 अक्टूबर, 2023 को दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान महासप्तमी के अवसर पर विभिन्न पूजा पंडालों का दर्शन कर पूजा-अर्चना करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

अजमेर (राजस्थान) में 18 अक्टूबर, 2023 को भाजपा संभाग बैठक के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 11 अक्टूबर, 2023 को तंजानिया की राष्ट्रपति सुश्री सामिया सुलुहू हसन से मुलाकात करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) में 16 अक्टूबर, 2023 को 'परिवर्तन संकल्प रैली' के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

जगदलपुर (छत्तीसगढ़) में 19 अक्टूबर, 2023 को 'परिवर्तन संकल्प रैली' के दौरान अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्रों (तेलंगाना) में 16 अक्टूबर, 2023 को एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 राजस्थान की जनता देगी भाजपा को आशीर्वाद : जगत प्रकाश नड्डा

कोटा में संभाग बैठक को संबोधित करने के पश्चात् मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जो उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में और भाजपा को लेकर यहां की जनता में दिख रहा है, उससे यह...

11 भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंजानिया की राष्ट्रपति से भेंट की

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 अक्टूबर, 2023 को...

12 यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई...

22 प्रधानमंत्री ने 'नमो भारत' रैपिडएक्स ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा...

32 आपका सपना ही मेरा संकल्प है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 'द सिंधिया स्कूल' के 125वें संस्थापक दिवस के...

लेख

महिला आरक्षण विधेयकः ऐतिहासिक सुधार / **जी किशन रेड्डी** 26
नदियों की भूमि और विकसित भारत का सपना / **सर्बानंद सोनोवाल** 28
नारी उत्थान के क्षेत्र में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय / **राजकुमार चाहर** 30

श्रद्धांजलि

वरिष्ठ भाजपा नेता सरताज सिंह नहीं रहे 21

अन्य

तेलंगाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया है : राजनाथ सिंह 08
भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है : अमित शाह 09
कैबिनेट ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी 14
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9 अक्टूबर, 2023 तक 17.95 प्रतिशत बढ़कर 11.07 लाख करोड़ रुपये हुआ 15
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के तहत बने 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड 16
मोदी स्टोरी 20
कमल पुष्प 21
भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए कुशल पेशेवर तैयार कर रहा है: प्रधानमंत्री 24
'इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेसः मन की बात @100' 33

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ. प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बनेगी।

(20 अक्टूबर, 2023)

जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनसंघ ने स्वतंत्र भारत में नई राजनैतिक परंपरा का शुभारंभ कर राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा, राष्ट्र प्रथम की नीति, 'एक भारत—श्रेष्ठ भारत' की दृष्टि और राजनीतिक शुचिता को समस्त भारतवासियों में स्थापित किया। आज 'भारतीय जनसंघ' के स्थापना दिवस पर हमारे संस्थापक आदर्शों को नमन करता हूं। राष्ट्रोत्थान का आपका संकल्प हमारी प्रेरणा है, यह प्रतिपल हमें जनकल्याण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

(21 अक्टूबर, 2023)

अमित शाह

राजनीतिक इशारे पर किए गए 1984 के दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दोषियों को जेल भेजने का काम मोदीजी ने शुरू किया। साथ ही, मोदी सरकार ने दंगों के 3,328 पीड़ितों के परिवार को 5 लाख रुपए देने का काम भी किया।

(13 अक्टूबर, 2023)

राजनाथ सिंह

कृषि एवं किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हमेशा प्रथम प्राथमिकता रही है। आज कैबिनेट की बैठक में रबी की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय से न केवल किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य प्राप्त होगा, बल्कि उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। किसानों के हित को ध्यान में रखकर लिये गये इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्रीजी का आभार!

(18 अक्टूबर, 2023)

बी.एल. संतोष

ठेकेदार संघ के उपाध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस पार्षद के पति के घर से आईटी छापे में 42 करोड़ रुपये जब्त किए गए। आरोप है कि इसे तमिलनाडु के रास्ते तेलंगाना ले जाया जाना था। कर्नाटक सत्ताधारी पार्टी के लिए एटीएम बन गया है।

(13 अक्टूबर, 2023)

पीयूष गोयल

भारत की संसाधन क्षमता को उजागर किया गया! स्वदेशी खनन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों– लिथियम, नायोबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी।

(11 अक्टूबर, 2023)

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
दीपावली (12 नवंबर)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

ऊंचे एवं महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को छू रहा आज का भारत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'नमो भारत' ट्रेन का झंडी दिखाकर शुभारंभ होते ही भारत को अपना पहला रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस) का उपहार मिल गया। इससे 'कनेक्टिविटी' के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है जिससे नगरों के मध्य आवागमन में यात्रियों को कई नई सुविधाएं, तीव्रता एवं आधुनिकता उपलब्ध होंगी। आरआरटीएस जो अंतर-नगरीय आवागन के लिए 180 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार तक की सेवा उपलब्ध कराएगी, यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा एवं समय की बचत करने में सक्षम होगी। यह एक उत्कृष्ट, मेड-इन-इंडिया एवं विश्व में सर्वोत्तम आवागमन सेवा है जो मेट्रो एवं बस सेवा से जुड़ी हुई है तथा यात्रियों के लिए कई प्रकार से सुगम एवं सुलभ सेवा उपलब्ध कराएगी। पिछले नौ वर्षों में चाहे जलमार्ग हो, थल मार्ग हो, आकाश मार्ग हो या यहां तक कि अंतरिक्ष मार्ग हो, हर क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का उपयोग कर यात्रा एवं परिवहन के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। जहां नमो भारत एवं वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्प को दिखाता है, वहीं अमृत भारत के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा 'कनेक्टिविटी' पर विशेष ध्यान देने से न केवल उत्तर-पूर्व, लद्दाख, कश्मीर सहित अनेक क्षेत्रों का तीव्र विकास हो रहा है, बल्कि इससे औद्योगीकरण की भी गति तेज हुई है और अब तक दूरस्थ माने जाने वाले क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के भारी अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि 'नमो भारत' भविष्य के भारत की एक झलक है।

पिछले नौ वर्षों मे चाहे जलमार्ग हो, थल मार्ग हो, आकाश मार्ग हो या यहां तक कि अंतरिक्ष मार्ग हो, हर क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का उपयोग कर यात्रा एवं परिवहन के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है

रबी फसल के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की घोषणा से मोदी सरकार के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की प्रतिबद्धता पुनः प्रमाणित होती है। जहां मोदी सरकार किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुणा मूल्य निरंतर सुनिश्चित कर रही है, कई नए फसलें भी एमएसपी फसलों की सूची में जोड़ी गई हैं। गेहूं एवं कुसुम के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल तथा मसूर के लिए सर्वाधिक 450 रुपए प्रति क्विंटल एवं रेपसीड तथा सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ध्यान देने योग्य है कि पिछले नौ वर्षों में एमएसपी पर इन फसलों की सरकारी खरीदगी भी कई गुणा बढ़ी है जिससे किसानों की बड़ी संख्या में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हुआ है। किसान, कृषि एवं गांवों पर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आज कई योजनाएं, कार्यक्रमों एवं प्रकल्पों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में भारी विकास हुआ है और ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। जहां विश्व में कई देशों में उर्वरकों के मूल्य में भारी बढ़ोतरी दिख रही है, वहीं भारत में मोदी सरकार द्वारा भारी अनुदान देकर उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित कर स्थिर रखा गया है। इससे देशभर में किसानों को भारी राहत मिली है। पीएम-किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान ऋण पोर्टल, एफपीओ का शुभारंभ, कृषि संबंधित क्षेत्र जैसे मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, बागवानी आदि में अनेक अभिनव योजनाओं के जरिए पूरे देश में किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। परिणाम यह है कि देश के अन्नदाता भी हर वर्ष रिकार्ड उत्पादन कर देश का मान बढ़ा रहे हैं।

अब जबकि आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान में वृद्धि की है, भारत पूरे विश्व में सबसे तेज गति वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आज भारत को चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के मध्य एक चमकता सितारा के रूप में देखा जा रहा है। आज अनेक बड़ी उपलब्धियों के कारण पूरे राष्ट्र का मनोबल तो बढ़ा ही है, साथ ही अब देश की नजरें ऊंचे लक्ष्यों पर केंद्रित है। चंद्रयान-3 और आदित्य एल-1 के सफल प्रक्षेपण तथा जी-20 के अत्यंत सफल आयोजन के बाद गगनयान मिशन का भी सफल परीक्षण हुआ है। अब लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एवं 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का नया एवं महत्वाकांक्षी स्वप्न अवश्य साकार होगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

राजस्थान की जनता देगी भाजपा को आशीर्वाद : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 एवं 18 अक्टूबर, 2023 को क्रमशः जोधपुर तथा कोटा एवं अजमेर संभाग में बैठकें कर पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किए और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने संभाग पदाधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए राजस्थान सहित पूरे देश में गरीबों के जन-कल्याण कार्य एवं विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में किए गए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाएं। साथ ही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, दलित, आदिवासी एवं महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करें

कोटा में संभाग बैठक को संबोधित करने के पश्चात् मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जो उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में और भाजपा को लेकर यहां की जनता में दिख रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना मन बना लिया है। राजस्थान की जनता ने संकल्प ले लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। जनता निश्चित रूप से कांग्रेस की भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और भाजपा को आशीर्वाद देगी। भाजपा को कोटा की सभी 17 सीटों पर विजय मिलेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि जनमानस में देखता हूं कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में हर दिन औसतन 17 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लगभग 22 प्रतिशत बलात्कार के मामले अकेले राजस्थान में हो रहा है। यहां नाबालिग बच्चियों के रेप की लगभग 15 हजार से अधिक घटनाएं दर्ज की गई है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार महिला उत्पीड़न में राजस्थान नम्बर एक पर है। करौली में दलित बहन के साथ किस तरह का पाशविक व्यवहार किया गया, इससे न केवल राजस्थान बल्कि पूरा देश शर्मिंदा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवा भी कांग्रेस की सरकार से परेशान बैठे हैं। राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुआ है। 19 हजार से अधिक किसानों की भूमि को जब्त किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा करते थे लेकिन कर्जमाफी तो दूर, किसानों की जमीन कुर्क कर ली गई। लाल डायरी पर जिस तरह से कांग्रेस नेता बेशर्मी से जवाब देते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार पर उदासीन है।

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह मर्दों की भूमि है, इसलिए बलात्कार होता है। समझा जा सकता है कि ऐसी सोच वाले नेता और ऐसे राजनीतिक दल महिलाओं के प्रति किस तरह की दुर्भावना रखते हैं। ऐसी पार्टी को और ऐसे नेताओं को कोटा सहित पूरे राजस्थान की जनता भरपूर मजा चखाएगी और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी।

श्री नड्डा ने संभागों के पदाधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में पिछले पांच साल से राजस्थान में लूट-खसोट का शासन-प्रशासन चल रहा है। अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करते हुए जनता का हालबेहाल कर

दिया है। राजस्थान की जनता आए दिन पेपर लीक, माइनिंग घोटाला, सचिवालय में करोड़ों रुपए कैश पकड़े जाने जैसे मामलों से जनता त्राहिमाम कर रही है। कांग्रेस की सरकार में नौकरियों की परीक्षा में रिश्वतखोरी हो रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो राजस्थान के युवा अब नहीं सहेंगे। अशोक गहलोत कैबिनेट के एक मंत्री जब एक लाल डायरी को सार्वजनिक करते हुए अपने ही सरकार पर साक्ष्य के साथ भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। राजस्थान में किसानों से लेकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, युवा, महिला—सब गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार से अत्यंत दुःखी हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि भाजपा के कार्यकर्ता घर-घर जाकर अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को जागरूक करें।

सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए श्री नड्डा ने कहा कि पिछले पांच सालों में कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में प्रदेश में कानून व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि राजस्थान में रोज औसतन 17 से 18 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध आज राजस्थान में हो रहे हैं, यह अत्यंत दुःखद है। जबकि, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नारी शक्ति के सशक्तीकरण के लिए विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। श्री नड्डा ने संभाग पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से मिलें और उन्हें गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध के खिलाफ जागरूक करें। ■

अजमेर

'अशोक गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अजमेर संभाग में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि हमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा गरीबों के लिए किये गये कल्याणकारी कार्यों तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को राजस्थान में जन-जन तक पहुंचाना है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर-घर जाकर लोगों को राज्य की गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करें। उन्होंने पदाधिकारियों से हर चुनावी रैली में भ्रष्टाचार, कदाचार और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों को उजागर करने को भी कहा।

कार्यकर्ताओं से बात करते हुए श्री नड्डा ने कहा, "अशोक गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रदेश में बढ़ते अपराधों से हर व्यक्ति परेशान है। यहां आए दिन पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत कैबिनेट के एक मंत्री ने लाल डायरी सार्वजनिक कर उनके भ्रष्टाचार की पुष्टि की है।"

श्री नड्डा ने कहा कि ऐसे हजारों मामले हैं जिनमें मानवता शर्मसार होती है, लेकिन हमने उनको लेकर भी गहलोत सरकार की उदासीनता देखी है। उन्होंने कहा कि 17 पेपर लीक के मामले सामने आये हैं और 50 लाख से ज्यादा युवाओं के साथ अन्याय हुआ। इसलिए युवाओं ने भी मन बना लिया है कि वे इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं।

किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलित हैं। वे सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जब किसान और जनता मिलकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जवाब देंगे। श्री नड्डा ने कांग्रेस के पाखंड, महिला उत्पीड़न और 'लाल डायरी' से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। ■

जोधपुर

'प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिलेगी'

राजस्थान के झालावाड़-बारां में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को छोटी टोली में इन समुदाय के धार्मिक स्थल पर जाने की प्रथा भी बनानी चाहिए।

श्री नड्डा ने कहा कि युवाओं को संवेदनशील बनाने और उन्हें भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए नेताओं को खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनके साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी नेताओं को फुटबॉल या क्रिकेट मैदानों या जिमों में जाकर लोगों तक पहुंच बनानी चाहिए और युवाओं की समस्याओं को सुनना चाहिए एवं उनके समाधान का रास्ता निकालना चाहिए।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में जबरदस्त उत्साह है और उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में भाजपा को भारी जीत मिलेगी। ■

तेलंगाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया है : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में आगामी विधान सभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान को गति प्रदान करते हुए 16 अक्टूबर, 2023 को हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के जम्मीकुंटा और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बदंगपेट में चुनावी सभाओं को संबोधित किया।

केसीआर का पूरा परिवार सरकार चला रहा है

श्री सिंह ने हुजूराबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास और शासन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "पिछले 10 सालों में तेलंगाना में विकास सिर्फ सीमित नहीं, बल्कि निजी तौर पर सीमित हुआ है। यहां केसीआर के परिवार का दखल सबसे ज्यादा है। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आपके परिवार को नहीं। मैं आपके किसी परिवारजन पर आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं उन सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन सरकार आपको चलानी है। केसीआर का पूरा परिवार सरकार चला रहा है। तेलंगाना के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। केसीआर के शासन में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। केसीआर का कहना है कि उन्होंने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन उनके परिवार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की बात हैदराबाद या तेलंगाना तक ही सीमित नहीं है, यह दिल्ली तक पहुंच गयी है।"

हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं

श्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक नेताओं के शब्दों और उनके कार्यों के मेल के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "नेता ऐसा होना चाहिए जो वह बोलता है वही करता है। उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर ने भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा कर दिया है। अगर भारत में किसी पार्टी ने विश्वसनीयता के इस संकट को दूर किया है, तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा है। हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं।"

कितने लाभार्थियों को 3 एकड़ जमीन मिली?

श्री सिंह ने केसीआर से दलितों को तीन एकड़ जमीन और प्रति परिवार 10 लाख रुपये का अनुदान देने के उनके वादे के बारे में भी सवाल किया और पूछा कि कितने लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा, "केसीआर के शासन में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है।"

उन्होंने दावा किया कि मोदी शासन में महिलाओं को अधिक अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक, जो हाल ही में संसद में पारित हुआ है, 2026 या 2029 में भी लागू हो सकता है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री परुषोत्तम रूपाला और अन्य वरिष्ठ नेता भी तेलंगाना में भाजपा के चुनावी अभियान के तहत रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होने हैं। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमिलनाडु दौरे के लिए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने तमिलनाडु का दौरा करने के लिए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। इससे पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिकायत कर कहा था कि प्रदेश सरकार उनके साथ 'क्रूर और तर्कहीन व्यवहार' कर रही है।

22 अक्टूबर, 2023 को जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगा।

इस बयान के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें सांसद और पूर्व पुलिस आयुक्त (मुंबई) श्री सत्यपाल सिंह, आंध्र प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी और सांसद श्री पी.सी. मोहन शामिल होंगे। ■

भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर, 2023 को राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नामांकन में हिस्सा लिया और इससे पहले उन्होंने स्टेट स्कूल मैदान, राजनांदगांव में आयोजित भाजपा की विशाल परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। श्री शाह के साथ सभा में राजनांदगांव प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, डोंगरगढ़ से भाजपा प्रत्याशी श्री विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भाजपा प्रत्याशी श्री भरत वर्मा एवं खुज्जी से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती गीता साहू भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अरुण साव, सांसद सुश्री सरोज पांडेय एवं बिरनपुर हिंसा में मारे गए भुनेश्वर साहू के पिता एवं भाजपा प्रत्याशी श्री ईश्वर साहू सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। श्री शाह ने जनसभा में गर्जना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार करने की पराकाष्ठा करते हुए छत्तीसगढ़ में "30 टक्का भूपेश कका सरकार" बनाकर चलाया है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस दरबार का एटीएम बना दिया, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, केवल गांधी परिवार खुशहाल है।

श्री शाह ने कहा कि श्री भूपेश बघेल की तुष्टीकरण और वोटबैंक की राजनीति के कारण छत्तीसगढ़ के बेटे भुनेश्वर साहू को लिन्चिंग करवाकर मार दिया गया। भाजपा ने तय किया है कि हम श्री भुनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसलिए भाई भुनेश्वर साहू के पिता श्री ईश्वर साहू को भाजपा ने छत्तीसगढ़ चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। आज राजनांदगांव में प्रत्याशियों का नामांकन रैली में इतना विशाल जनसमूह मेरे सामने है, आपका उत्साह देखकर मैं भरोसा लेकर जा रहा हूं कि 3 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है।

> **भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस दरबार का एटीएम बना दिया, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, केवल गांधी परिवार खुशहाल है**

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान देकर इसे राजभाषा बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया। किसानों को 14 प्रतिशत ब्याज से मुक्त करने का काम हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। देशभर मे पीडीएस सबसे अच्छी और सुचारु व्यवस्था छत्तीसगढ़ में रहीं, जिसके परिणामस्वरूप डॉ. रमन सिंह को जनमानस द्वारा चावल-वाला-बाबा कहकर भी पुकारा गया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव एक सरकार बनाने या विधायक चुनने का चुनाव नहीं हैं, बल्कि आने वाला चुनाव मोदीजी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के भविष्य को स्वर्णिम बनाने का चुनाव है। प्रत्येक छत्तीसगढ़िया का एक-एक वोट मोदीजी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ी बनाने के लिए देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 15 साल के शासन में छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को खाद और पोषण की सुरक्षा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना। चाहे कौशल विकास के अधिकार की बात हो या 150 दिन तक रोजगारी सुनिश्चित करने की, महिला मजदूर को मातृत्व अवकाश मिलने की या राज्य कि माताओं-बहनों को पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना।

श्री शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के दलित युवा और पिछड़े वर्ग के लोगों का पैसा भी इस एटीएम (श्री भूपेश बघेल) की मदद से कांग्रेस के दिल्ली दरबार की तिजोरी में भरा जाता है। जैसे फूड चेन बनते हैं, ठीक वैसे ही भूपेश बघेल की सरकार ने पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक के करप्शन का चेन बनाया। भूपेश बघेल की सरकार ने करप्शन चेन बनाकर छत्तीसगढ़ को लूटा और लूट का पैसा दिल्ली तक पहुंचा। घोटालों की इतनी बड़ी सूची, मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखी। 2,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 550 करोड़ का कोयला परिवहन घोटाला, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5,000 करोड़ का घोटाला किया, 1,300 करोड़ से ज्यादा का गौठान घोटाला, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, साथ ही महादेव एप का 5,000 करोड़ का घोटाला—यह सब इस भूपेश बघेल सरकार में हुआ। भूपेश सरकार ने तो बच्चों की नौकरियों को भी नहीं छोड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन करके बच्चों की नौकरियों में भी कटकी (कमिशन) लेने का काम किया है। भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि यहां लोगों को विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदीजी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार चाहिए। ■

जगदलपुर एवं कोंडागांव (छत्तीसगढ़)

भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 19 अक्टूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और कोंडागांव में आयोजित विशाल परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन रैलियों को संबोधित किया और प्रदेश की जनता से भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।

श्री शाह ने जगदलपुर की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था लेकिन

यह समस्या अब धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने आगे जनता से आग्रह करते हुए कहा कि एक बार छत्तीसगढ़ में कमल की सरकार बना दीजिए, इस प्रदेश से हम पूर्ण रूप से नक्सल समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में नक्सली घटनाओं में 52 प्रतिशत, इसके कारण हुई मौतों में 70 प्रतिशत और नक्सल मुठभेड़ में आम नागरिकों की मृत्यु में लगभग 68 प्रतिशत और नक्सल प्रभावी जिलों की पुलिस चौकी व थानों में 62 प्रतिशत हिंसक घटनाओं की कमी देखने को मिली है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर घोटालों का आरोप मढ़ते हुए श्री शाह ने बताया कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब बेचने की दुकानें खुलवाई और 2000 करोड़ रुपये का घोटाला किया, कोयले के परिवहन में 540 करोड़ रुपये का घोटाला किया, गरीबों के अनाज में 5000 करोड़ का घोटाला हुआ और गोठान में 1300 करोड़ रुपये का घोटाला किया। बघेल सरकार की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत घोटालों के बारे में सुना है, लेकिन गाय के गोबर में कोई (भूपेश बघेल) 1300 करोड़ रुपये खा जाये, ऐसा आदमी मैंने पहले कहीं नहीं देखा। भूपेश बघेल सरकार में 600 करोड़ रुपये का बीडीएस घोटाला, 5000 करोड़ रुपये का महादेव एप घोटाला हुआ।

श्री शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने 36 लाख किसानों को उनके खातों में हर साल 6000 रुपए सहायता के तौर पर दिए गए व 32 लाख गरीब लोगों को नल से जल देने का काम भी किया। मोदी सरकार ने लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य मुफ़्त में देने, 30 लाख महिलाओं को शौचालय, 35 लाख महिलाओं को गैस सिलिंडर और 2 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो चावल निःशुल्क देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित की है। ■

बुद्धिजीवी वर्ग के साथ संवाद, सिकंदराबाद (तेलंगाना)

'कांग्रेस और बीआरएस ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 10 अक्टूबर, 2023 को सिकंदराबाद, तेलंगाना में प्रोफेशनल्स और बुद्धिजीवी वर्ग के साथ संवाद किया और उनसे तेलंगाना के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जी. किशन रेड्डी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद श्री सैयद ज़फ़र इस्लाम सहित पार्टी के कई गणमान्य नेता उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि तेलंगाना की जनता के सामने तीन विकल्प हैं— पहला भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कांग्रेस और तीसरा वर्तमान में शासन कर रही बीआरएस है। आपने कांग्रेस और बीआरएस, दोनों का शासन देखा है। दोनों ने यहां के गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार देखी है। एक मौक़ा तेलंगाना में भी दीजिये, हम तेलंगाना को 5 साल में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करेंगे।

श्री शाह ने 2013 में देश के परिदृश्य को याद दिलाते हुए कहा कि देश में उस समय कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी और सारी वंशवादी पार्टियों का जमघट 10 साल से देश पर शासन कर रहा था। 2013 में इस देश की स्थिति क्या थी, इससे हम सभी अवगत हैं। तत्कालीन समय में देश के अंदर एक अविश्वास फैला था कि भारत का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस के शासन में कभी हाई कोर्ट के द्वारा, कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो कभी विजिलेन्स कमीशन के द्वारा कुल 12 लाख करोड़ रुपये के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार एक के बाद एक बाहर आ रहे थे। जनता के बीच में एक भारी अविश्वास का माहौल बन गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारी सृष्टि पूरी धाराशाही हो गई है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, देश की राजधानी दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह चरमराई हुई थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी देश के अंदर घुसकर बम-धमाका करते थे, जवानों के सिर काटकर ले जाते थे, दिल्ली की सरकार में मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ्फ तक नहीं करते थे, विदेशों के अंदर देश की साख नीचे जा रही थी, युवाओं मे तत्कालीन सरकार के खिलाफ आक्रोश था, घपले घोटालों व करप्शन से देश आतंकित था, आज सरकार के 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेन्द्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंजानिया की राष्ट्रपति से भेंट की

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया की राष्ट्रपति महामहिम सुश्री सामिया सुलुहू हसन से भेंट की, जो तंजानिया की सत्तारूढ़ पार्टी चामा चा मापिन्दुज़ी (सीसीएम) की अध्यक्ष भी हैं।

इस मुलाकात के दौरान श्री नड्डा ने संयुक्त गणराज्य तंजानिया की राष्ट्रपति को भाजपा के दृष्टिकोण और संगठनात्मक स्वरूप से अवगत कराया। उन्होंने गरीबों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए पार्टी की सामाजिक समावेशन पहल पर भी चर्चा की। उन्होंने व्यापक आबादी से जुड़ने के लिए पार्टी द्वारा प्रयोग की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में भी बताया। दोनों नेताओं ने भविष्य में भी इस तरह का पार्टी से पार्टी के बीच संवाद जारी रखने का संकल्प लिया।

इससे पहले सीसीएम के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने 'भाजपा को जानें' पहल के तहत पार्टी के निमंत्रण पर जनवरी महीने में भारत का दौरा किया था। महामहिम सुश्री सामिया सुलुहू हसन ने 2021 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का दायित्व संभाला था। वह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इस बैठक में महामहिम सुश्री सामिया सुलुहू हसन के साथ सीसीएम के कई नेता भी मौजूद थे। वहीं, इस अवसर पर भाजपा के विदेश विभाग के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले भी उपस्थित रहे। ■

त्रिपुरा और ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने श्री इंद्र सेना रेड्डी नल्लू और श्री रघुबर दास को क्रमशः त्रिपुरा और ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति सचिवालय से 18 अक्टूबर, 2023 को जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया, 'भारत की राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करती हैं: श्री इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल और श्री रघुबर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।'

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास को ओडिशा का 26वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री श्री इंद्र सेना रेड्डी नल्लू तीन बार आंध्र प्रदेश के विधायक रह चुके हैं। ■

संगठनात्मक नियुक्ति

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जतिंदर पाल मल्होत्रा को चंडीगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 13 अक्टूबर, 2023 को श्री जतिंदर पाल मल्होत्रा को चंडीगढ़ भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। भाजपा की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ■

यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले में लगभग 4200 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग 4200 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कीं।

लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा पर उत्तराखंड के लोगों के अभूतपूर्व प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया और कहा, "यह स्नेह की गंगा बहने की तरह था।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैद्यनाथ धाम में जय बद्री विशाल के उद्‌घोष से गढ़वाल राइफल्स के जवानों का जोश और उत्साह बढ़ता है और गंगोलीहाट के काली मंदिर में घंटियों की ध्वनि कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों में नए साहस का संचार करती है। मानसखंड में श्री मोदी ने बैद्यनाथ, नंदादेवी, पूर्णागिरि, कसारदेवी, कैंचीधाम, कटारमल, नानकमत्ता, रीठा साहिब और अनेक अन्य मंदिरों का उल्लेख किया, जो इस भूमि की भव्यता और विरासत को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं आपके बीच उत्तराखंड में होता हूं, हमेशा खुद को धन्य समझता हूं।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन किए। "मैंने प्रत्येक भारतीय के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत की मजबूती का संकल्प लेते हुए प्रार्थना की। मैंने आशीर्वाद मांगा कि उत्तराखंड के लोगों की सभी आकांक्षाएं पूरी हों।"

श्री मोदी ने सैनिकों, कलाकारों और स्वयं सहायता समूहों के साथ अपनी बैठकों का भी उल्लेख किया और सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति के स्तंभों के मिलने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार उत्तराखंड के लोगों की प्रगति और जीवन को आसान बनाने के लिए पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ काम कर रही है।"

श्री मोदी ने उत्तराखंड के साथ अपने लंबे जुड़ाव और निकटता को याद किया। 'नारीशक्ति वंदन अधिनियम' के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य से मिले समर्थन और प्रतिक्रिया का उल्लेख किया।

5 वर्षों में 13.5 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी के दुष्चक्र से बाहर

श्री मोदी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आए हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार के सर्व-समावेशी दृष्टिकोण को श्रेय दिया, जिसके तहत दूरदराज के

स्थानों में रहने वाले लोगों को भी सरकारी लाभ मिलता है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, 'दुनिया आश्चर्यचकित है' क्योंकि 13.5 करोड़ लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये 13.5 करोड़ लोग इस बात के उदाहरण हैं कि भारत अपनी क्षमता से ही देश की गरीबी को खत्म कर सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि भले ही पिछली सरकारों ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था, लेकिन यह 'मोदी' है, जो कहता है कि स्वामित्व और जिम्मेदारी लेकर गरीबी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम एक साथ मिलकर गरीबी मिटा सकते हैं।" श्री मोदी ने भारत के चंद्रयान का उल्लेख किया, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहा और इसने वह उपलब्धि हासिल की, जिसे अब तक कोई देश प्राप्त नहीं कर सका है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "जिस स्थान पर चंद्रयान उतरा, उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है और इस प्रकार उत्तराखंड की पहचान अब चंद्रमा पर भी मौजूद है।" उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कदम-कदम पर शिव शक्ति योग देखने को मिलता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक

श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के हर गांव ने भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैन्य कर्मियों को जन्म दिया है। उन्होंने उल्लेख

किया कि वर्तमान सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' की उनकी दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 'वन रैंक वन पेंशन' योजना के तहत पूर्व सैनिकों को अब तक 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है, जिससे पूर्व सैनिकों के 75,000 से अधिक परिवारों को अत्यधिक लाभ हुआ है। उन्होंने कहा, "सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।"

श्री मोदी ने कहा कि जीवंत ग्राम योजना ने देश के आखिरी गांवों को पहले गांवों में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारा प्रयास उन लोगों को वापस लाना है, जो इन गांवों को छोड़ चुके हैं। हम इन गांवों में पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इन क्षेत्रों में नई सुविधाओं और अवसंरचनाओं का निर्माण हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सड़कों, सिंचाई सुविधाओं और आज शुरू की गई पॉलीहाउस योजना से सेब की खेती को फायदा होगा। इन परियोजनाओं पर 1100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने कहा, "उत्तराखंड के हमारे छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तहत उत्तराखंड के किसानों को अब तक 2200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।"

संबोधन का समापन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह भारत का अमृत काल है। उन्होंने कहा, "यह समय देश के हर क्षेत्र एवं हर वर्ग को सुविधाओं, सम्मान और समृद्धि से जोड़ने का है।" उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बाबा केदार और बद्री विशाल के आशीर्वाद से देश अपने संकल्पों को शीघ्रता से पूरा कर सकेगा। ■

भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसनथुरई के बीच 40 वर्ष बाद शुरू हुई नौका सेवा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अक्टूबर को वीडियो संदेश के माध्यम से भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसनथुरई के बीच नौका सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित किया।

सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका राजनयिक और आर्थिक संबंधों की दिशा में एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं और नागपट्टिनम और कांकेसनथुरई के बीच नौका सेवाओं का शुभारंभ दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारत और श्रीलंका के बीच संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता के साझा इतिहास को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागपट्टिनम और इससे जुड़े हुए आसपास के शहर श्रीलंका सहित कई देशों के साथ समुद्री व्यापार के लिए जाने जाते रहे हैं और प्राचीन तमिल साहित्य में भी पूंपुहार के ऐतिहासिक बंदरगाह को प्रमुख केन्द्र बताया गया है। उन्होंने पट्टिनप्पलाई और मणिमेकलाई जैसे संगम युग के साहित्य के बारे में भी अपने विचार रखे, जिसमें दोनों देशों के बीच नौका सेवा और समुद्री जहाजों के परिचालन का वर्णन है।

श्री मोदी ने वर्ष 2015 में अपनी श्रीलंका यात्रा को याद किया जब दिल्ली और कोलंबो के बीच सीधी उड़ान शुरू की गई थी। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका से तीर्थ नगरी कुशीनगर में पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान के आने का उत्सव भी मनाया गया था। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि चेन्नई और जाफना के बीच सीधी उड़ान वर्ष 2019 में आरंभ की गई थी और अब नागपट्टिनम और कांकेसनथुरई के बीच नौका सेवा इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि प्रगति और विकास के लिए साझेदारी भारत-श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों के सबसे मजबूत आधार स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा, "हमारा विजन विकास को सभी तक ले जाना है, किसी को भी इससे वंचित नहीं रखना है।"

श्री मोदी ने बताया कि श्रीलंका में भारत की सहायता से कार्यान्वित परियोजनाओं ने लोगों के जीवन को नया रूप दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तरी प्रांत में आवास, जल, स्वास्थ्य और आजीविका सहायता से संबंधित कई परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कांकेसनथुरई बंदरगाह के प्रगतिकरण के लिए समर्थन देने में प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "चाहे उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली रेलवे लाइनों की बहाली हो; प्रतिष्ठित जाफना सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण; पूरे श्रीलंका में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू करना; डिक ओया में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के विजन के साथ कार्य कर रहे हैं।" ■

कैबिनेट ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी

न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दाल (मसूर) के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल दी गई तथा रेपसीड एवं सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल व गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 18 अक्टूबर को विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दाल (मसूर) के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल और इसके बाद रेपसीड एवं सरसों के लिए

विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं	फसलें	एमएसपी आरएमएस 2014-15	एमएसपी आरएमएस 2023-24	एमएसपी आरएमएस 2024-25	उत्पादन लागत आरएमएस 2024-25	एमएसपी में वृद्धि (संपूर्ण)	लागत पर मार्जिन (प्रतिशत में)
1	गेहूं	1400	2125	2275	1128	150	102
2	जौ	1100	1735	1850	1158	115	60
3	चना	3100	5335	5440	3400	105	60
4	दाल (मसूर)	2950	6000	6425	3405	425	89
5	रेपसीड एवं सरसों	3050	5450	5650	2855	200	98
6	कुसुम	3000	5650	5800	3807	150	52

200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं और कुसुम में से प्रत्येक के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। जौ और चने के लिए क्रमशः 115 रुपये प्रति क्विंटल और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।

विपणन सीजन 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई थी। अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूं के लिए 102 प्रतिशत; रेपसीड और सरसों के लिए 98 प्रतिशत; दाल के लिए 89 प्रतिशत; चने के लिए 60 प्रतिशत; जौ के लिए 60 प्रतिशत और कुसुम के लिए 52 प्रतिशत है। रबी फसलों की इस बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और श्रीअन्न/मोटे अनाजों की ऊपज बढ़ाने के क्रम में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। मूल्य नीति के अलावा, सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने व तिलहन और दलहन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) जैसी विभिन्न पहलें की हैं। ■

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9 अक्टूबर, 2023 तक 17.95 प्रतिशत बढ़कर 11.07 लाख करोड़ रुपये हुआ

प्रत्यक्ष कर संग्रह के 9 अक्टूबर, 2023 तक जो अनंतिम आंकड़े सामने आए हैं उनमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई तथा सकल संग्रह 11.07 लाख करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के सकल संग्रह से 17.95% अधिक है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड का शुद्ध (नेट रिफंड) 9.57 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के शुद्ध संग्रह से 21.82% अधिक है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के अनुमानित कुल बजट का 52.50% है।

जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) की वृद्धि दर का सवाल है, सीआईटी के लिए विकास दर 7.30% है, जबकि पीआईटी के लिए 29.53% (केवल पीआईटी)/ 29.08% (एसटीटी सहित पीआईटी) है।

रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 12.39% है और पीआईटी संग्रह में 32.51% (केवल पीआईटी)/31.85% (एसटीटी सहित पीआईटी) है। 1 अप्रैल, 2023 से 09 अक्टूबर, 2023 के दौरान 1.50 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किए गए। ■

खुदरा महंगाई सितंबर में तीन महीने के निचले स्तर 5.02 प्रतिशत पर

महंगाई दर में यह गिरावट खाने का सामान, पेय पदार्थ, ईंधन और रोशनी खंडों की महंगाई में उल्लेखनीय कमी आने से आई है तथा मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति 4.7 प्रतिशत रही जो फरवरी, 2020 के बाद सबसे कम है

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से 12 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित (सीपीआई) मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 5.02 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने अगस्त में 6.83 प्रतिशत थी। महंगाई दर में यह गिरावट खाने का सामान, पेय पदार्थ, ईंधन और रोशनी खंडों की महंगाई में उल्लेखनीय कमी आने से आई है।

इस दौरान मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति 4.7 प्रतिशत रही जो फरवरी, 2020 के बाद सबसे कम है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में से खाद्य, पेय और ईंधन तथा रोशनी क्षेत्रों को हटाने पर मुख्य मुद्रास्फीति प्राप्त की जाती है।

एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में खाने के सामान की कीमतें घटने से खाद्य मुद्रास्फीति 6.56 प्रतिशत पर आ गई जबकि अगस्त में यह 9.94 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी करीब आधी है।

सब्जियों के मामले में महंगाई दर सितंबर में घटकर 3.39 प्रतिशत पर आ गई, जो अगस्त में 26.14 प्रतिशत थी। ■

देश में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अगस्त में 14 महीने के उच्चतम स्तर 10.3 प्रतिशत पर

विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में अगस्त में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 14 महीने का उच्च स्तर है। खनन उत्पादन 12.3 प्रतिशत बढ़ा, वहीं बिजली उत्पादन में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 12 अक्टूबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अगस्त में 14 महीने के उच्चतम स्तर 10.3 प्रतिशत पर रही। उपयोग आधारित वर्गीकरण के तहत छह में से तीन क्षेत्रों में दहाई अंक में वृद्धि दर्ज की गयी। इससे पहले, जून, 2022 में औद्योगिक उत्पादन में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में अगस्त में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 14 महीने का उच्च स्तर है। खनन उत्पादन 12.3 प्रतिशत बढ़ा, वहीं बिजली उत्पादन में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अगस्त, 2023 के महीने के लिए 2011-12 के आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान 145.1 है। जुलाई, 2023 के महीने के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 111.9, 143.5 और 220.5 पर हैं।

उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार जुलाई, 2023 के महीने के लिए प्राथमिक वस्तुओं के लिए सूचकांक 145.4, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 107.0, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 156.1 और बुनियादी ढांचे/निर्माण वस्तुओं के लिए 175.5 पर हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता के लिए गैर-टिकाऊ वस्तुओं का सूचकांक अगस्त, 2023 के महीने के लिए क्रमशः 122.8 और 147.0 पर हैं। ■

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के तहत बने 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) ने 19 अक्टूबर, 2023 को देशभर में 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। इस महत्वपूर्ण योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें 12 करोड़ लाभार्थी परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पताल इलाज के लिये प्रति परिवार पांच लाख रुपये वार्षिक स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है।

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के तहत आयुष्मान कार्ड तैयार करना सबसे प्रमुख कार्य है और इसके लिये लगातार गहन प्रयास किये जा रहे हैं कि योजना के तहत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी के पास उसका आयुष्मान कार्ड हो। यह आयुष्मान भवः अभियान के तहत होने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में संतृप्ति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से की गई है। 13 सितंबर, 2023 को अभियान शुरू किये जाने के बाद से एनएचए के आईटी प्लेटफार्म पर 1.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड आवेदनों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। अक्टूबर, 2023 महीने में ही 19 अक्टूबर तक 86 लाख आयुष्मान कार्ड तैयार कर लिये गये।

एनएचए ने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 'आयुष्मान ऐप' लॉन्च किया है। ऐप में स्वतः सत्यापन की विशिष्ट सुविधा है। उपयोगकर्ता चार सरल कदम उठाने से ही एप से आयुष्मान कार्ड बना सकता है। इसके लिये उसे किसी कार्ड सृजन केन्द्र पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनाने में लाभार्थी की मदद कर सकता है। इस प्रकार आयुष्मान एप जनभागीदारी में भी सक्षम है। एप्पलीकेशन की सफलता को इस तथ्य से ही आंका जा सकता है कि 13 सितंबर, 2023 को इसकी शुरुआत के बाद से ही इसे 26 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के तहत 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय के साथ 5.7 करोड़ अस्पताल भर्ती मामलों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस प्रकार गरीब और वंचित परिवारों के एक लाख करोड़ रुपये से अधिक जेब खर्च की बचत इससे हुई। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी

केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 01 जुलाई, 2023 से महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी, जो मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन की 42 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 4 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12,857 करोड़ रुपये होगा। इससे केंद्र सरकार के करीब 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। ■

तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों लिथियम, नायोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर को तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों लिथियम, नायोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) के संबंध में रॉयल्टी की दर तय करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 ('एमएमडीआर अधिनियम') की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दे दी।

हाल ही में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 17 अगस्त, 2023 से लागू हो गया है। संशोधन के जरिये अन्य बातों के अलावा, लिथियम और नायोबियम सहित छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है, जिससे नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को इन खनिजों के लिए रियायतें देने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा, संशोधन में प्रावधान किया गया है कि लिथियम, नायोबियम और आरईई (यूरेनियम और थोरियम रहित) के साथ 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों (जो अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग डी में सूचीबद्ध हैं) के खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्तशासी निकाय 'मेरा युवा भारत' की स्थापना को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर को 'मेरा युवा भारत' (एमवाई भारत) नाम के एक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य युवाओं के विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करना और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करते हुए उनकी आकांक्षाओं को साकार करना और सरकार के संपूर्ण दायरे में विकसित भारत का निर्माण करना है।

मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। नई व्यवस्था के तहत युवा, संसाधनों तक पहुंच और अवसरों से जुड़ाव के साथ, परिवर्तन के एजेंट और राष्ट्र निर्माता बन जाएंगे और सरकार तथा नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य कर सकेंगे। यह व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग करेगी।

मेरा युवा भारत (एमवाई भारत), एक स्वायत्तशासी निकाय होगा। राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई 'युवा' की परिभाषा के अनुरूप 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा इससे लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले में लाभार्थी 10-19 वर्ष के आयु वर्ग के होंगे।

मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) की स्थापना से इन बिन्दुओं को बढ़ावा मिलेगा:

क. युवाओं में नेतृत्व विकास

- अलग-अलग व्यक्तिगत संपर्क की जगह प्रोग्रामेटिक कौशल का विकास कर अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार होगा।
- युवाओं में अधिक निवेश करके उन्हें सामाजिक नवाचार और समुदाय नेता बनाने का कार्य किया जाएगा।
- युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना और युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का 'सक्रिय चालक' बनाना।

ख. युवा आकांक्षाओं और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल।

ग. मौजूदा कार्यक्रमों का सम्मिलन कर युवाओं की दक्षता में वृद्धि करना।

घ. युवा लोगों और मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना।

ड. एक केंद्रीकृत युवा डेटा बेस बनाना।

च. युवा सरकारी पहलों और युवाओं के साथ जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों को जोड़ने के लिए दोतरफा संचार में सुधार।

छ. एक भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए पहुंच सुनिश्चित करना। ■

बागवानी उत्पादन रिकार्ड 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 18 अक्टूबर को विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के लिए वर्ष 2022-23 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया। इसके अनुसार वर्ष 2022-23 में देश में कुल बागवानी उत्पादन रिकार्ड 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में खाद्यान्न के साथ ही बागवानी का भी लगातार रिकार्ड उत्पादन हो रहा है, जो हमारे किसान भाइयों-बहनों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता तथा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों का सद्परिणाम है।

वर्ष 2021-22 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) की मुख्य बातें:

- वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 (अंतिम) की तुलना में लगभग 4.74 मिलियन टन (1.37%) की बढ़ोतरी है।
- फलों, सब्जियों, वृक्षारोपण फसलों, फूलों व शहद के उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है।
- फलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 के 107.51 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2022-23 में 108.34 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 212.91 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021-22 में 209.14 मिलियन टन था।
- वृक्षारोपण फसलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 15.76 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 16.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो लगभग 1.78% की वृद्धि है।
- आलू का उत्पादन 60.54 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 56.18 मिलियन टन था। ■

लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए मिली मंजूरी

यह परियोजना वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 18 अक्टूबर को लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) चरण-II-अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) परियोजना को स्वीकृति दी।

वित्त वर्ष 2029-30 तक स्थापित होने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ रुपये है। परियोजना को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 40 प्रतिशत यानी 8,309.48 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

लद्दाख क्षेत्र के जटिल भू-भाग, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और रक्षा सीमाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) इस परियोजना को लागू करने वाली एजेंसी होगी। अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर (वीएससी) आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) सिस्टम और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट (ईएचवीएसी) प्रणाली लगाई जाएगी।

बिजली ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर हरियाणा के कैथल तक जाएगी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। लेह में इस परियोजना से मौजूदा लद्दाख ग्रिड तक इंटरकनेक्शन की भी योजना बनाई गई है, ताकि लद्दाख को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसे जम्मू-कश्मीर को बिजली प्रदान करने के लिए लेह-अलुस्टेंग-श्रीनगर लाइन से भी जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में पांग (लद्दाख) और कैथल (हरियाणा) में 713 किमी ट्रांसमिशन लाइनें (480 किमी एचवीडीसी लाइन सहित) और 5 गीगावॉट क्षमता वाले हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल की स्थापना शामिल होगी।

यह परियोजना वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी। इससे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा विकसित करने और कार्बन उत्सर्जन कम करके पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में बिजली और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल और अकुशल दोनों कर्मियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे। ■

पीएम गतिशक्ति की 7,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे की योजना बनाने में रही महत्वपूर्ण भूमिका

पीएम गतिशक्ति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की तैयारी में भी क्रांति ला दी है, इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को 6-9 महीने से घटाकर केवल कुछ घंटों का कर दिया है

13 अक्टूबर को जारी 'पीएम गतिशक्ति का सार-संग्रह' के अनुसार पिछले दो वर्षों में पीएम गतिशक्ति 7,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे की योजना बनाने में महत्वपूर्ण रही है, जिसमें जीआईएस मानचित्रों के माध्यम से डिजिटल सर्वेक्षणों से क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में तेजी आई है। वर्ष 2022-23 में 400 से अधिक परियोजनाओं के साथ नई रेलवे लाइनों के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या केवल 57 थी, जिसके परिणामस्वरूप 13,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों की योजना बनाई गई।

इस मंच ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की तैयारी में भी क्रांति ला दी है, इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को 6-9 महीने से घटाकर केवल कुछ घंटों का कर दिया है, जिससे वनों की कटाई को कम करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति वचनबद्धता प्रदर्शित की गई है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पीएम गतिशक्ति के दो साल पूरे होने के अवसर पर 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में 'पीएम गतिशक्ति का सार-संग्रह' जारी किया।

इस सार-संग्रह में आठ अनुकरणीय उपयोग के मामले पूरे देश में पीएम गतिशक्ति को व्यापक रूप से अपनाने और गहन लाभों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इन मामलों में परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक्सप्रेसवे और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की योजना, रेल मंत्रालय द्वारा रेल कनेक्टिविटी योजना, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित ऊर्जा गलियारों की योजना और उत्तर प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करने आदि जैसी पहल शामिल है। यह सार-संग्रह हितधारकों के लिए पीएम गतिशक्ति के लाभों एवं उपयोगिता को प्रदर्शित करने और व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करेगा। ■

आईएमएफ ने 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत किया

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने भारत की 2023-24 की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान 0.2 प्रतिशत बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, इसने वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया।

आईएमएफ के 10 अक्टूबर को 'विश्व आर्थिक परिदृश्य' में चीन के वृद्धि के अनुमान को 2023 के लिए 0.2 प्रतिशत और 2024 के लिए 0.3 प्रतिशत घटाकर क्रमशः पांच प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर चीन से अधिक रहने का अनुमान है।

इसमें कहा गया है कि भारत में वृद्धि दर 2023 और 2024 दोनों में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस तरह आईएमएफ ने 2023 के लिए अपने पूर्वानुमान में 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अप्रैल-जून के दौरान उम्मीद से अधिक मजबूत खपत के चलते ऐसा किया गया है।

आईएमएफ ने कहा कि मौद्रिक नीति अनुमानों के मुताबिक मध्यम अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।

भारत विकास एवं नवाचार का एक पावरहाउस: प्रधानमंत्री

आईएमएफ के विकास संबंधी पूर्वानुमान पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को कहा कि भारत वैश्विक स्तर का एक उज्ज्वल स्थान तथा विकास एवं नवाचार का एक पावरहाउस है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसा हमारे लोगों की शक्ति और कौशल के कारण है।

उन्होंने यह प्रतिबद्धता भी दोहराई है कि हम अपने सुधारों के पथ को और आगे बढ़ाते हुए समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करना जारी रखेंगे। आईएमएफ के एक्स थ्रेड्स पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लोगों की शक्ति और कौशल से संचालित, भारत वैश्विक स्तर का एक उज्ज्वल स्थान तथा विकास एवं नवाचार का एक पावरहाउस है। हम अपने सुधारों के पथ को और आगे बढ़ाते हुए समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करना जारी रखेंगे। ■

पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 3.21 करोड़ घरों का हुआ निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण पहल के रूप में 67,000 से अधिक 'अमृत सरोवर' का निर्माण किया गया

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएमएवाई-जी (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.21 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है। इन पिछले 9 वर्षों में लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए कुल 2.48 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

गौरतलब है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में 'ग्रामीण विकास की 9 वर्षों की उपलब्धियों' पर यह जानकारी दी।

प्रमुख उपलब्धियां

- वर्ष 2014 से डीएवाई-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के अंतर्गत कुल 7.33 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में सम्मिलित किया गया।
- बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋण की राशि 7.22 लाख करोड़ से अधिक है। यह प्रशंसनीय है कि वर्ष 2014 के बाद से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रतिशत घटकर 1.88 प्रतिशत हो गया है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य अब दिसंबर, 2023 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की दीदियों तक पहुंचना और कम से कम 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना है।
- पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के अंतर्गत कुल 7.44 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़क पूरी हो चुकी है और 1.62 लाख से अधिक ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ा गया है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों के दौरान कुल 2,644 करोड़ व्यक्ति दिवस सृजित किए गए हैं और 6.63 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी की गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण पहल के रूप में 67,000 से अधिक 'अमृत सरोवर' का निर्माण किया गया। ■

मोदी स्टोरी

गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए प्रधानमंत्री मोदीजी की प्रतिबद्धता

— मनसुख मंडाविया

श्री नरेन्द्र मोदी ने शासन में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की, जिसने गुजरात में समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मार्ग प्रशस्त किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर, 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्होंने गुजरात के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए मिशन मोड़ में कार्य किया।

मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई नीतियों ने राज्य के शासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने का कार्य किया, इसके लिए श्री मोदी ने साहसिक निर्णय लिये और उनके साथ मजबूती से खड़े रहे।

गुजरात राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की समस्या थी। इस कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। इनमें से अधिकतर मामले ग्रामीण गुजरात से थे, जहां बिजली की पर्याप्त सप्लाई के अभाव में कुछ लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा था।

केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि कैसे श्री मोदी ने बड़े पैमाने पर हो रही इस बिजली चोरी की समस्या पर अंकुश लगाया।

इसके तहत मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार राज्य में बिजली चोरी नहीं होने देगी। श्री मोदी ने सभी के लिए मीटर लगवाना अनिवार्य कर दिया।

मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई नीतियों ने राज्य के शासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने का कार्य किया, इसके लिए श्री मोदी ने साहसिक निर्णय लिये और उनके साथ मजबूती से खड़े रहे

उनके इस फैसले का जमकर विरोध हुआ और राज्य सरकार के खिलाफ कई आंदोलन हुए। उस समय हम सभी उनके निर्णय के बारे में निश्चित नहीं थे।

उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें यह सुझाव भी दिया कि वह इस फैसले पर आगे न बढ़ें, क्योंकि इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा और आगामी चुनावों में इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। मेरी बात सुनने के बाद श्री मोदी ने मुझे बताया कि राज्य में असली समस्या बिजली नहीं बल्कि पानी की आपूर्ति है।"

कुछ समय बाद उन्होंने जल आपूर्ति में सुधार के लिए काम करना शुरू किया और चेक डैम बनाये, जिसे उन्होंने एक मिशन के रूप में लिया।

उन्होंने मनरेगा योजना के तहत 'बोरी बांध' बनाने की शुरुआत की और एक साल तक यह अभियान चलाया। इस अभियान के परिणामस्वरूप हर छोटी सड़क को 'बोरी बांध' योजना से जोड़ा गया। परिणामस्वरूप, राज्य में जल स्तर बढ़ने लगा और जो स्थान पहले 'ब्लैक जोन' के अंतर्गत आते थे, वे भी पानी से समृद्ध हो गये। इससे पानी की कमी की समस्या खत्म हो गयी।

अपने निर्णय पर आगे बढ़ते हुए श्री मोदी ने घोषणा की कि मीटर वाले कनेक्शनों पर नियमित रूप से आठ घंटे बिजली दी जायेगी और बिजली चोरी बंद हो जायेगी।

इसके बाद न केवल बिजली का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया, बल्कि पानी की कमी से भी निपटा गया। आठ घंटे बिजली की उपलब्धता किसानों के लिए उपयोगी साबित हुई। यह मुख्यमंत्री श्री मोदी द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। ■

वरिष्ठ भाजपा नेता सरताज सिंह नहीं रहे

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सरताज सिंह का 12 अक्टूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वर्गवास हो गया। वह 83 वर्ष के थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी और तीन बेटियां हैं।

श्री सिंह मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। उन्होंने होशंगाबाद सीट से पांच बार लोकसभा चुनाव जीता। वह दो बार विधायक भी चुने गये।

उन्होंने 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक केंद्रीय कैबिनेट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का दायित्व संभाला।

श्री सिंह 1998 में होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से शक्तिशाली कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह को हराने के बाद चर्चा में आए। ■

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता श्री सरताज सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

- जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

केंद्र व मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री रहे श्री सरताज सिंह जी के निधन का दुःखद समाचार सुनकर मन व्यथित है। भगवान से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिवारजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

- शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

कमल पुष्प सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

दुव्वुरी राधाकृष्ण रेड्डी

आंध्र प्रदेश के मायपाडु निवासी श्री दुव्वुरी राधाकृष्ण रेड्डी वर्ष 1965-67 के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा में मुख्य शिक्षक रहे। उन्होंने आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह में भाग लिया और नेल्लोर में एक वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे। वह एक सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भाजपा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन किया। ■

श्री दुव्वुरी राधाकृष्ण रेड्डी

जन्म: 01 जून, 1951

सक्रिय वर्ष: 1972-2012

जिला: नेल्लोर

प्रधानमंत्री ने 'नमो भारत' रैपिडएक्स ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिडएक्स स्टेशन पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के शुभारंभ को चिह्नित करते हुए साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली 'नमो भारत' रैपिडएक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व-पश्चिम गलियारे की दो लाइनों को भी राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा 'नमो भारत' ट्रेन देशवासियों को समर्पित की जा रही है। श्री मोदी ने चार वर्ष पहले दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के शिलान्यास को याद किया और आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो खंड पर इसके संचालन को चिह्नित किया। उन्होंने उन परियोजनाओं का उद्घाटन करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जिनका शिलान्यास किया जा चुका है और विश्वास व्यक्त किया कि डेढ़ साल बाद आरआरटीएस के मेरठ खंड के पूरा होने पर वह उसका उद्घाटन करने के लिए उपस्थित भी रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने रीजनल रैपिड ट्रेन 'नमो भारत' में यात्रा की

प्रधानमंत्री ने रीजनल रैपिड ट्रेन 'नमो भारत' में यात्रा की। श्री मोदी ने नमो भारत में अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया और देश में रेलवे के कायापलट पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि नव उद्घाटित नमो भारत ट्रेन में सहायक स्टाफ और लोकोमोटिव पायलट सभी महिलाएं हैं। श्री मोदी ने कहा, "नमो भारत देश में नारीशक्ति के बढ़ते कदमों का प्रतीक है।"

प्रधानमंत्री ने नवरात्र के शुभ अवसर पर आज प्राप्त होने वाली परियोजनाओं के लिए दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, "नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।"

श्री मोदी ने कहा, "21वीं सदी का भारत हर क्षेत्र में प्रगति और विकास की अपनी दास्तान लिख रहा है।" उन्होंने भारत को समूची दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने वाली चंद्रयान 3 की सफलता और जी-20 के सफल आयोजन का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक अपने नाम करने वाले रिकॉर्ड प्रदर्शन, भारत में 5जी की शुरुआत और विस्तार तथा रिकॉर्ड संख्या में हो रहे डिजिटल लेन-देन का उल्लेख किया।

विनिर्माण क्षेत्र में भारत के उदय का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उत्सुकता के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने कहा, "नमो भारत ट्रेन भी मेड इन इंडिया है।" उन्होंने कहा कि प्लेटफार्मों पर स्थापित स्क्रीन डोर भी भारत में निर्मित हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि नमो भारत ट्रेन में आवाज का स्तर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की तुलना में कम है।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि 'नमो भारत' भविष्य के भारत की झलक है और इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है, तो कैसे देश की तस्वीर बदलने लगती है। उन्होंने कहा कि यह 80 किलोमीटर का दिल्ली मेरठ खंड सिर्फ शुरुआत भर है, क्योंकि पहले चरण में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्रों को नमो भारत ट्रेन से जोड़ा जाएगा।

बेंगलुरु मेट्रो की दो लाइनें राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेंगलुरु में मेट्रो की दो लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने जिन दो मेट्रो लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया, उनमें बैयप्पनहल्ली को कृष्णराजपुरा और केंगेरी को चैल्लाघट्टा से जोड़ने वाले खंड शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि औपचारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा किए बिना इस गलियारे पर जनता को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए इन दो मेट्रो खंडों को 9 अक्टूबर, 2023 से सार्वजनिक सेवा के लिए खोल

दिया गया था।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारा

- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिकता वाला खंड गाजियाबाद, गुलधार और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को 'दुहाई डिपो' से जोड़ेगा।
- प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2019 को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ गलियारा की आधारशिला रखी थी।
- आरआरटीएस एक नई रेल-आधारित, सेमी हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वैन्सी वाली कम्यूटर ट्रांज़िट प्रणाली है।
- 180 किमी प्रति घंटे की गति के साथ आरआरटीएस एक परिवर्तनकारी, क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसे हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई-स्पीड ट्रेनें प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आवश्यकता के अनुसार हर 5 मिनट की फ्रीक्वैन्सी तक जा सकती है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तैयार किए जाने वाले कुल आठ आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिनमें से तीन कॉरिडोर को चरण-I में लागू करने की प्राथमिकता दी गई है, जिसमें दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर; दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर कॉरिडोर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर शामिल है।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है और यह गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर के शहरी केंद्रों से गुजरते हुए एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा।
- देश में विकसित आरआरटीएस एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय गतिशीलता समाधान है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ से इसकी बराबरी की जा सकती है। यह देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। ■

प्रधानमंत्री ने जी-20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वें जी-20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी-20) का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की संसद द्वारा भारत की जी-20 अध्यक्षता की व्यापक संरचना के तहत 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद' की थीम के साथ की जा रही है।

श्री मोदी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से जी-20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन विश्वभर की सभी संसदीय प्रथाओं का एक 'महाकुंभ' है।

श्री मोदी ने कहा कि पी-20 शिखर सम्मेलन उस भूमि पर आयोजित हो रहा है जो न केवल लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। विश्वभर की विभिन्न संसदों के प्रतिनिधियों के रूप में प्रधानमंत्री ने बहस और विचार-विमर्श के महत्व को रेखांकित किया और अतीत में हुई ऐसी बहसों के सटीक उदाहरणों का उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि भारत के पांच हजार वर्ष पुराने वेदों और शास्त्रों में विधानसभाओं और समितियों का उल्लेख मिलता है, जहां समाज के कल्याण के लिए सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। भारत के सबसे पुराने धर्मग्रंथ ऋग्वेद की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने एक संस्कृत श्लोक का पाठ किया जिसका अर्थ है 'हमें एक साथ चलना चाहिए, एक साथ बोलना चाहिए और हमारे विचार आपस में जुड़े होने चाहिए।'

प्रधानमंत्री ने समय के साथ भारत की संसदीय परंपराओं के निरंतर विकास और सदृढ़ीकरण पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद से भारत में 17 आम चुनाव और 300 से अधिक विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है।

श्री मोदी ने कहा कि 2019 का आम चुनाव, जब उनकी पार्टी सत्ता में चुनी गई, मानव इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी, क्योंकि 600 मिलियन मतदाताओं ने इसमें भाग लिया था। उन्होंने कहा कि उस समय 910 मिलियन पंजीकृत मतदाता थे, जो पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी अधिक थी। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के बीच 70 प्रतिशत मतदान भारतीयों की संसदीय प्रथाओं में गहरी आस्था को दर्शाता है। 2019 के चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई।

राजनीतिक भागीदारी के विस्तारित होते कैनवास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले आम चुनाव में 600 से अधिक राजनीतिक दलों ने भाग लिया और 10 मिलियन सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव के संचालन में काम किया और मतदान के लिए एक मिलियन मतदान केंद्र बनाए गए।

श्री मोदी ने प्रतिनिधियों को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के हाल के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों में 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "भारत आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा हाल में लिया गया निर्णय हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा।" ■

भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए कुशल पेशेवर तैयार कर रहा है: प्रधानमंत्री

प्रत्येक केन्द्र कम से कम दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे।

ग्रामीण कौशल्य विकास केन्द्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रत्येक केन्द्र कम से कम दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् के तहत सूचीबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। इन केन्द्रों की स्थापना से संबंधित इलाके को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के आरंभ में यह कहा कि यह नवरात्रि का 5वां दिन है, जब स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह देखते हुए कि हर मां अपने बच्चों के लिए खुशी और सफलता की कामना करती है, श्री मोदी ने रेखांकित किया कि इसे केवल शिक्षा और कौशल विकास से ही संभव बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की स्थापना के बारे में बोलते हुए कहा कि आज का दिन लाखों युवाओं के कौशल विकास के लिए एक बड़ा कदम है, जो इस दिन को स्मरणीय बनाता है।

श्री मोदी ने कहा कि विश्व स्तर पर कुशल भारतीय युवाओं की मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कई देशों की जनसंख्या में बढ़ती आयु प्रोफ़ाइल का उल्लेख करते हुए एक अध्ययन को साझा किया, जिसमें कहा गया है कि 16 देशों ने लगभग 40 लाख कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए कुशल पेशेवर तैयार कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कौशल केंद्र स्थानीय युवाओं को वैश्विक नौकरियों के लिए तैयार करेंगे और उन्हें निर्माण, आधुनिक कृषि, मीडिया तथा मनोरंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौशल प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने बुनियादी विदेशी भाषा कौशल, भाषा व्याख्या के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग करने वाले सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। यह प्रशिक्षण नियोक्ताओं के लिए और अधिक आकर्षक बन जाएगा।

1 करोड़ 30 लाख से अधिक युवाओं को मिला प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि वर्तमान सरकार ने कौशल विकास की आवश्यकता को समझा और इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया, जिसके पास अपना बजटीय आवंटन है और विभिन्न योजनाएं हैं।

श्री मोदी ने बताया कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न विशेषज्ञताओं के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा पूरे देश में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं।

कौशल विकास के इन प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्रकार के उन कौशलों में सुधार पर जोर दिया, जो देश को और मजबूत करेंगे। उन्होंने भारत के विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) उद्योग में अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों या दोषरहित उत्पादों की आवश्यकता को रेखांकित किया और उद्योग 4.0 के बारे में भी चर्चा की, जिसके लिए नए कौशल की आवश्यकता है।

संबोधन की मुख्य बातें

- ये केंद्र हमारे युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसरों का लाभ लेने में प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे
- कुशल भारतीय युवाओं की मांग विश्व स्तर पर बढ़ रही है
- सरकार ने कौशल विकास की आवश्यकता को समझा और इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया, जिसके पास अपना बजटीय आवंटन है और विभिन्न योजनाएं हैं
- सरकार की कौशल विकास पहल का सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को मिल रहा है
- महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण पर सरकार के विशेष ध्यान की प्रमुख प्रेरणास्रोत सावित्री बाई फुले रही हैं
- पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाएगी
- उद्योग 4.0 को नए कौशल से लैस लोगों की आवश्यकता होगी
- देश की विभिन्न राज्य सरकारों को कौशल विकास के अपने दायरे को और बढ़ाना होगा ■

‘ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023’

प्रधानमंत्री ने ‘अमृत काल विज़न 2047’ का किया अनावरण

पिछले दशक में भारत में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में 17 अक्टूबर को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने ‘अमृत काल विजन 2047’ का भी अनावरण किया जो भारतीय समुद्री क्षेत्र के लिए नीली अर्थव्यवस्था की मूल योजना (ब्लूप्रिंट) है। इस भविष्यवादी योजना के अनुरूप प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए ‘अमृत काल विजन 2047’ से जुड़ी हैं। यह शिखर सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण में मौजूद सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने 2021 में शिखर सम्मेलन को याद करते हुए कहा कि कैसे उस वक्त पूरी दुनिया कोविड महामारी की अनिश्चितताओं से जूझ रही थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज एक नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है।

बदलती विश्व व्यवस्था में श्री मोदी ने विशेष तौर पर कहा कि दुनिया नई उम्मीदों के साथ भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से जूझ रही दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। वैश्विक व्यापार में समुद्री मार्गों की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना के बाद की आज की दुनिया में एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर ऐतिहासिक जी20 सर्वसम्मति के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया। श्री मोदी ने कहा कि जैसे अतीत के सिल्क रूट ने कई देशों की अर्थव्यवस्था बदल दी, वैसे ही यह गलियारा भी वैश्विक व्यापार की तस्वीर बदल देगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोहराया कि आज का भारत अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने बताया कि सरकार हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। उन्होंने भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले दशक में भारत में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो गई है और बड़े जहाजों के लिए जहाज पर से माल उतारने और लादने का समय 2014 में 42 घंटे की तुलना में अब 24 घंटे से भी कम हो गया है। ■

नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फ़ेडरेशन को 50 हजार करोड़ रुपये का टर्नओवर प्राप्त कर ‘आत्मनिर्भर’ बनना चाहिये: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फ़ेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) के निदेशक मंडल को संबोधित किया। श्री अमित शाह ने कहा कि NCCF को वर्ष 2027-28 तक 50 हजार करोड़ रुपये का टर्नओवर प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना चाहिये।

उन्होंने कहा कि NCCF को देश भर की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और अन्य सहकारी संस्थाओं को अपना सदस्य बनाने पर जोर देना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि NCCF की अंश पूंजी में सहकारिता का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इसके लिये NCCF को अपना बिज़नेस प्लान डेवलप करने तथा बिज़नेस एप्रोच में बदलाव लाना होगा।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विज़न को पूरा करने में NCCF महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, अपने गठन के बाद से, सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और GDP में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पिछले 26 महीनों में 52 पहल की है। ■

महिला आरक्षण विधेयक: ऐतिहासिक सुधार

जी किशन रेड्डी

जैसे ही ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसके पारित होने को सांसदों के लिए अग्निपरीक्षा की संज्ञा कहकर संबोधित किया। यह अग्निपरीक्षा वास्तव में थी—भारत के पारंपरिक गौरव को बहाल करने के लिए अग्निपरीक्षा, जो समानता और संतुलन के साथ खड़ी थी; अग्निपरीक्षा उस सर्वोच्च स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए जिसका लाभ प्राचीन काल से महिलाओं को मिलता आया है; और राजनीतिक बाध्यताओं से ऊपर उठकर नारी शक्ति के लिए एक साथ खड़े होने के लिए अग्नि परीक्षा थी। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, को अर्धनारीश्वर की भावना का प्रतीक होना चाहिए और इसे नारी शक्ति द्वारा लाई गई समानता और पूर्ण संतुलन का प्रतीक होना चाहिए।

लैंगिक असमानता और अन्याय से जूझ रही दुनिया में भारत महिलाओं के प्रति श्रद्धा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सदियों से भारतीय संस्कृति ने महिलाओं को शक्ति के अवतार के रूप में मनाया है। विद्वानों, योद्धाओं, रानियों और नेताओं के रूप में उनकी क्षमताओं को पहचाना है। चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो, जहां महिलाओं को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्रकट करने वाली त्रिदेवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। महिला विद्वानों द्वारा रचित भजनों के साथ वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथ; या प्राचीन सभ्यताएं, जहां योद्धा रानियों ने अपने राज्यों को जीत और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। प्राचीन भारत में महिलाएं न केवल शिक्षित थीं बल्कि दार्शनिक चर्चाओं और धार्मिक समारोहों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। भारत ने गार्गी, लोपामुद्रा और मैत्रेयी जैसे प्रसिद्ध दार्शनिकों और विद्वानों, वीरांगनाओं जैसे पद्मिनी, रानी दुर्गावती, रानी रुद्रमादेवी, रानी अहिल्याबाई होल्कर और ऐसी कई महान महिलाओं को देखा है, आधुनिक दुनिया में भी हमने वर्षों पहले ही उन्हें मतदान का अधिकार भी दिया।

प्राचीन भारत में महिलाएं न केवल शिक्षित थीं बल्कि दार्शनिक चर्चाओं और धार्मिक समारोहों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। भारत ने गार्गी, लोपामुद्रा और मैत्रेयी जैसे प्रसिद्ध दार्शनिकों और विद्वानों, वीरांगनाओं जैसे पद्मिनी, रानी दुर्गावती, रानी रुद्रमादेवी, रानी अहिल्याबाई होल्कर और ऐसी कई महान महिलाओं को देखा है, आधुनिक दुनिया में भी हमने वर्षों पहले ही उन्हें मतदान का अधिकार भी दिया

शक्ति परंपरा का महत्व

रामायण और महाभारत में सीता माता, द्रौपदी और कुंती जैसी मजबूत और प्रभावशाली महिलाओं को दर्शाया गया है, जिन्होंने इन महाकाव्य गाथाओं की कहानियों और घटनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के प्रति सम्मान पारिवारिक परिवेश में उनकी भूमिकाओं तक भी फैला हुआ है। वह सह धर्मचारिणी हैं, जिसका अर्थ है कि वह गृहस्थ धर्म में एक समान भागीदार हैं, जहां वह अपने पति के साथ घर का नेतृत्व करती हैं और सभ्यता को धर्म के मार्ग पर ले जाती हैं। विशिष्ट रूप से सनातन धर्म में शक्ति परंपरा है, जिसमें नारी शक्ति या दिव्य मां के रूप में उनकी भक्ति की जाती है।

इन सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिध्वनित करते हुए एक संस्कृत उद्धरण समाज के वास्तुकार के रूप में महिलाओं की भूमिका को खूबसूरती से व्यक्त करता है:

नारी समाजस्य कुशलवस्तुकार:

कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय नारी को बहुत सम्मान प्राप्त था, एक परंपरा जो अनगिनत पीढ़ियों तक चली। हालांकि, बार-बार होने वाले विदेशी हमलों ने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं में निहित इस स्त्री महत्व को खत्म कर दिया है। नतीजतन, आधुनिक भारत में राजनीतिक प्रतिबद्धता और पहल की कमी के कारण विधायिकाओं (संघ और राज्य दोनों) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पिछड़ गया है।

2014 के बाद से मोदीजी ने भारत की लैंगिक समानता को फिर से व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया है। इसकी शुरुआत महिला विकास से आगे बढ़कर महिला-नेतृत्व वाले विकास के मिशन के रूप में हुई। नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा के मूल में रखा गया है। चाहे महिलाओं को उनके सशक्तीकरण में सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान करना हो या यह सुनिश्चित करना हो कि वे पूरी ताकत से आगे बढ़ें, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा रहा है जहां महिलाओं, जो कि भारत की 50 प्रतिशत आबादी है, को अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए समान अवसर मिल सकें।

छोटे चरणों में कल्याण उपायों को अपनाने की हमारी पिछली प्रथाओं से इतर

मोदी सरकार ने 2014 के बाद महिला के जीवन चक्र और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी विकास यात्रा को सहयोग दिया है। उनमें से सबसे बुनियादी बात यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं सम्मान और सुरक्षित जीवन जियें। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ धुआं-मुक्त रसोई सुनिश्चित की गयी है, जिसने न केवल लाखों महिलाओं को जीवनयापन में आसानी हुई है, बल्कि उन्हें श्वास संबंधी बीमारियों से भी बचाया है; स्वच्छ भारत योजना के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाये गये है, जिसने महिलाओं को शौचालयों तक सुरक्षित और सम्मानजनक पहुंच प्रदान की है, इसने सुरक्षा संबंधी उनकी चिंताओं को दूर किया है और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया है; इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ नल जल कनेक्शन दिये गये है। इन सभी उपायों ने महिलाओं को कठोर श्रम और वंचित जीवन से उबरने में मदद की है।

सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि दशकों से उपेक्षित सामाजिक परिवर्तन और सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ दिया गया है। चाहे वह महिलाओं की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना हो, मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना हो, या तीन तलाक प्रथा पर प्रतिबंध लगाना हो, इसी तरह, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ मिशन पूरे जोर-शोर से चलाया गया। लड़कियों के खिलाफ घृणित सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और परिणामस्वरूप, एनएफएचएस-5 की घोषणा के अनुसार अब प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं है, जो लिंग अनुपात में एक सकारात्मक सुधार की ओर इशारा करती हैं।

वास्तव में, मोदीजी नारी शक्ति के साथ खड़े रहे हैं क्योंकि वह शक्ति के अवतार के रूप में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही हैं।

महिला आरक्षण विधेयक उन इरादों की पुष्टि की मुहर है, एक शंखनाद है कि शक्ति जाग उठी है और हमारे महान राष्ट्र की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण विधेयक एक आधुनिक विचार है, जो महिलाओं को दिए गए प्राचीन सम्मान और समानता को दर्शाता है

जैसाकि स्पष्ट है प्रधानमंत्री श्री मोदी का महिला सशक्तीकरण का दृष्टिकोण ऐसा है, जो महिलाओं के जन्म से ही उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, कैरियर और रोजगार, पारिवारिक और मातृ-जीवन, राष्ट्र की सेवा और नेतृत्व की भूमिका निभाना शामिल है। महिला आरक्षण विधेयक उन इरादों की पुष्टि की मुहर है, एक शंखनाद है कि शक्ति जाग उठी है और हमारे महान राष्ट्र की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण विधेयक एक आधुनिक विचार है, जो महिलाओं को दिए गए प्राचीन सम्मान और समानता को दर्शाता है। यह विधेयक और प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में कई अन्य पहलों के साथ, हम अपनी ऐतिहासिक भूल में सुधार कर रहे हैं, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें भारत के मूल गौरव की ओर ले जाती है— एक ऐसी भूमि जहां महिलाओं की आवाज सुनी जाती थी, उनकी भूमिकाओं को स्वीकार किया जाता था और उनके योगदान को महत्व दिया गया।

भारतीय महिलाओं का सशक्तीकरण

गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मोदीजी द्वारा पेश महिला आरक्षण विधेयक को लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया, यह स्वयं विघ्नहर्ता का आशीर्वाद था, जिन्होंने माता पार्वती को उन्हें बनाने, उनका पोषण करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रणाम किया, ऐसे ही 22 सालों से इस बिल के समक्ष आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर महिलाओं को प्रणाम किया गया। इसके साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लैंगिक समानता और मां भारती और 140 करोड़ भारतीयों की भावना को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। मोदी है तो मुमकिन है एक बार फिर मेरे मन में गूंज उठा! ■

(लेखक तेलंगाना प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष तथा केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं विकास मंत्री हैं)

नदियों की भूमि और विकसित भारत का सपना

सर्बानंद सोनोवाल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी 2023 में वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। इस 51 दिवसीय क्रूज ने 27 विभिन्न नदी प्रणालियों में 3,200 किमी तक की यात्रा बिना किसी बाधा के तय की। इस दौरान क्रूज में सवार पर्यटकों को रास्ते में आने वाले 50 पर्यटन स्थलों पर हमारी विरासत, संस्कृति और शहरी परिदृश्य का अनुभव करने का मौका मिला। पिछले दशक में भारत ने परिवहन प्रणाली के प्रति अपने दृष्टिकोण में ऐसे कई परिवर्तनकारी बदलाव देखे हैं और इस विकास के केंद्र में हमारे पारंपरिक जलमार्ग नेटवर्क का पुनरुद्धार शामिल है।

भारत, नदियों की भूमि

सरकार के सुधार-केंद्रित दृष्टिकोण के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) प्रणाली को पर्यावरण-अनुकूल और लागत प्रभावी परिवहन मोड के रूप में विकसित करना है। एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लागू किया, जिसने वैज्ञानिक अध्ययन, विकास और संचालन के लिए परिवहन के 20,000 किमी से अधिक तक फैले 111 जलमार्गों की पहचान की।

इसके बाद, सागरमाला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना शुरू की गई, जिसमें जलमार्ग परिवहन के लिए कार्गो-विशिष्ट अवसरों की पहचान की गई, जिसके बाद अंतर्देशीय जहाज अधिनियम 2021 लागू हुआ, जिसने 1917 के शताब्दी पुराने कानून को बदल दिया। इन नीति सुधारों ने निवेश की एक नई लहर को जन्म दिया, साथ ही व्यापार करने में आसानी हुई और आर्थिक विकास को गति मिली।

नया IV अधिनियम इस क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के मार्ग को प्रशस्त करता है, राज्यों में इसे जुड़े नियमों को सुसंगत बनाता है, नेविगेशन सुरक्षा और कार्गो सुरक्षा मानकों को बढ़ाता है, प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाता है और अंतर्देशीय एवं तटीय जलमार्गों के एकीकृत विकास की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न हितधारकों के बीच कार्गो और बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी को निर्बाध रूप से साझा करने की अनुमति देने के लिए कार्गो डेटा पोर्टल (सीएआर-डी) और एसेट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन (पैनी) पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं, जिससे अधिक डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

विशाल सामाजिक-आर्थिक क्षमता को पहचानते हुए सरकार ने एनडब्ल्यू के विकास के लिए निवेश किए गए धन में भी 247 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके तहत 1986 से 2014 के बीच एनडब्ल्यू पर 1,517 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, जो 2014 और 2023 में बढ़कर 5,200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इससे 51,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं

इन सुधारों का प्रभाव राष्ट्रीय जलमार्ग कार्गो में छह गुना की वृद्धि में दिखता है, जो 2014 में 18.07 एमटीपीए से बढ़कर 2023 में 108.88 एमटीपीए हो गया है। यह सरकार की 'सुधार-प्रदर्शन-परिवर्तन' दृष्टि का एक उदाहरण है।

निवेश, कौशल विकास एवं रोजगार

प्रधानमंत्री ने एनडब्ल्यू-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) और एनडब्ल्यू-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) के साथ पूर्ण कायाकल्प, बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका सृजन के लिए 'अर्थ गंगा' और 'महाबाहु-ब्रह्मपुत्र' समग्र दृष्टिकोण दिया। संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण और शासन के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' मॉडल के साथ, भारत के 'जल राजमार्ग' तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन की रीढ़ बन गए हैं।

मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में आईडब्ल्यूटी कार्गो हिस्सेदारी को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने, 200 एमटीपीए की स्तर को पार करने और 2030 तक 700 मिलियन से अधिक यात्रियों को समायोजित करने की परिकल्पना की गई है। विशाल सामाजिक-आर्थिक क्षमता को पहचानते हुए सरकार ने एनडब्ल्यू के विकास के लिए निवेश किए गए धन में भी 247 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके तहत 1986 से 2014 के बीच एनडब्ल्यू पर 1,517 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, जो 2014 और 2023 में बढ़कर 5,200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इससे 51,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

हमने चरणबद्ध विकास के लिए 26 संभावित उच्च-यातायात राष्ट्रीय जलमार्गों को प्राथमिकता दी है। एनडब्ल्यू-1 और एनडब्ल्यू-2 की कुछ प्रमुख परियोजनाओं में वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी-मॉडल टर्मिनल, फरक्का में एक नेविगेशनल लॉक और जोगीघोपा, बोगीबील और डिब्रूगढ़ में यात्री-सह-कार्गो घाट शामिल हैं। कलिंगनगर, तालचेर और ओडिशा के अन्य औद्योगिक समूहों को एनडब्ल्यू-64 (महानदी नदी) और एनडब्ल्यू-5 के माध्यम से पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ने के लिए 22,000 करोड़ रुपये की मेगा जलमार्ग कनेक्टिविटी परियोजना भी विकसित की जा रही है। महाराष्ट्र में

एनडब्ल्यू-10 (अम्बा नदी) और एनडब्ल्यू-28 (दाभोल क्रीक-वशिष्ठी नदी) पर इसी तरह के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

अष्ट लक्ष्मी, भारत का नया विकास इंजन

प्रधानमंत्री के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पिछले दशक में परिवर्तनकारी विकास हुआ है और यह 21वीं सदी में भारत का नया विकास इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र को अग्रणी स्थिति में लाने के लिए समग्र योजना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2016 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की 20 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। पांडु बंदरगाह पर पूर्वोत्तर की पहली जहाज मरम्मत सुविधा के निर्माण सहित निर्बाध सड़क और रेल कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक रसद बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाले अंतर्देशीय जहाजों की मरम्मत का समय और लागत बहुत कम हो जाएगी।

इसके अलावा, युवा शक्ति की क्षमता का उपयोग करने के लिए 2023 में दो संस्थान स्थापित किए गए हैं– जिसमें गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल केंद्र और अगरतला में रसद, जलमार्ग और संचार स्कूल शामिल है। ये संस्थान विशाल प्रतिभा पूल का उपयोग करेंगे और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण का अग्रणी केंद्र बनाएंगे।

सरकार पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड बना रही है, जिसके तहत 5,000 किलोमीटर के नौगम्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का एक नेटवर्क विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। हम कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के संचालन में भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, जो भारत के पूर्वी तट से म्यांमार के सिटवे पोर्ट के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों तक वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिसका उद्घाटन मैंने इस साल मई में किया था। ये विकास आसियान और बिम्सटेक देशों के साथ भारत के पूर्वोत्तर के एकीकरण को बढ़ाएंगे, क्षेत्रीय विकास को गति देंगे, लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ाएंगे और गहरे व्यापार संबंध बनाएंगे।

भारत की विशाल समुद्री क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए मंत्रालय 'कनेक्ट— सहयोग— निर्माण' विषय के तहत 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई में तीसरे वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है। यह संस्करण उभरती समुद्री प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने और भारत के जहाज निर्माण, बंदरगाहों, अंतर्देशीय और तटीय जल परिवहन, समुद्री स्टार्ट-अप और अन्य क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए 70 से अधिक देशों के सरकारी तंत्र और व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं और 3,000 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को एक साथ ला रहा है। भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। ■

(लेखक भारत सरकार में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं)

पिछले एक दशक में आतंकवाद, उग्रवादी हमलों, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में 65% की कमी आई: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 अक्टूबर को 'पुलिस स्मृति दिवस' के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा और केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन की शुरुआत आज़ादी से अब तक देश की आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले 36,250 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से कहा कि आज भारत दुनिया में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इसकी नींव में शहीदों का बलिदान है और ये देश कभी उनके बलिदान को नहीं भुला सकेगा।

> **मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए सख्त कानून बनाये हैं**

श्री शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमलों, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में इसके सर्वोच्च स्तर से 65 प्रतिशत की कमी आई है।

श्री अमित शाह ने कहा कि विगत दिनों में NDRF के माध्यम से अलग-अलग पुलिसबलों के जवानों ने न केवल देश बल्कि दुनिया में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज जब हम आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार 3 नए क्रिमिनल लॉ लेकर आ रही है, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आमूलचूल रूप से बदल देंगे।

श्री शाह ने कहा कि अंग्रेज़ों के समय बनाए गए लगभग 150 वर्ष पुराने कानूनों की जगह लेने वाले इन 3 नए कानूनों में न सिर्फ भारतीयता दिखाई देगी, बल्कि हमारे संविधान की स्पिरिट से हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा भी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अदालतों में लंबित मामलों को समाप्त करने पर बल दिया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए सख्त कानून बनाये हैं और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 'पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन' की स्थापना करके विश्व का सर्वश्रेष्ठ आतंकवादरोधी बल बनने की दिशा में काम किया है। ■

नारी उत्थान के क्षेत्र में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय

राजकुमार चाहर

केवल नारी उत्थान नहीं, नारी के नेतृत्व में विकास की दृष्टि बीते चंद वर्षों में राष्ट्र की नीति बनी है। इसी नीति को अब वैश्विक एजेंडा बनाने के साथ ही भारत का नए संसद भवन में प्रवेश, भारत की नारी शक्ति के लिए विशेष अवसर बना। दशकों से लंबित विधायिका में महिला आरक्षण के सपने को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प ने यथार्थ में बदला, तो आम सहमति के नाम पर लटकने वाला बिल संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के साहसिक निर्णय, दृढ़ निश्चय और ईमानदार पहल से सहजता से कानून बन गया। अब लोकसभा-विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में रखे गए प्रावधान

(संविधान का 128वां संशोधन अधिनियम, 2023)

- इस बिल के माध्यम से आर्टिकल 339एए, 330ए, 332ए और 334ए में संशोधन किए गए।
- 339एए के माध्यम से 33 फीसदी सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- 330ए के माध्यम से लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली एक तिहाई सीटें (एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीट सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- 332ए के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे। अनुच्छेद के खंड-3 में एससी और एसटी सहित एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
- 334ए में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। भविष्य में जरूरत महसूस होने पर संसद को आरक्षण की अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।
- लोकसभा में अभी सीटों की संख्या 543 है। जैसे ही कानून लागू होगा, महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी जो वर्तमान में 82 है।

नए भारत की नई संसद में 20-21 सितंबर, नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक बन गया है। कभी राजनीति और सत्ता को सर्वोपरि मानकर जिस बिल को दशकों तक लटकाया गया या यूं कहें कि केवल बातें हुईं, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यथार्थ बना दिया। इसके लिए उन्होंने अवसर भी विशेष बना दिया और संसद के नए भवन में प्रवेश के लिए विशेष प्रयोजन के साथ विशेष सत्र बुलाया। अब जब भी नए संसद भवन की पहली शुरुआत की बात होगी, हर भारतवासी और विशेष रूप से नारी शक्ति का माथा गौरव से ऊंचा होगा।

दरअसल, नई संसद में राष्ट्र ने एक ऐसा इतिहास बनते देखा है, जिसकी कल्पना तो थी, लेकिन यथार्थ में बदलने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। नई संसद ने नया इतिहास रचा और यह अवसर नारी शक्ति के वंदन का अप्रतिम उदाहरण बन गया। आने वाली अनेक पीढ़ियों तक इस निर्णय और दिवस की चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 29 सितंबर को कानून बन चुका है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण अब सिद्धि बन गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है। यह नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। यह अमृतकाल में 'सबका प्रयास' से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा और बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, नारी के नेतृत्व में विकास का नया युग देश में लाने की जो गारंटी है, यह प्रधानमंत्री मोदीजी के संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लगभग तीन दशक से इस बिल को पारित कराने के लिए प्रयास हो रहा था। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह-तरह की बाधाएं थीं, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष-विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब-करीब सबने इसके पक्ष में वोट किया। अमृत काल की ओर बढ़ते भारत में नारी शक्ति, नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व का प्रतिबिंब बनी है क्योंकि वेदों और भारतीय परंपरा ने भी यही आह्वान किया है कि नारियां सक्षम हों, समर्थ हों और राष्ट्र को दिशा दें। अपने इसी दृष्टिकोण के साथ भारत ने जी-20 की अध्यक्षता करते हुए नारी शक्ति के नेतृत्व को अपनी प्राथमिकता में रख विश्व समाज को एक नई दिशा दी, तो अब नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल के रूप में पहला काम करके इतिहास रच दिया है।

असंभव को संभव कराती स्थिरता

महिला आरक्षण के लिए तीन दशकों से कोशिश और बातें हो रही थी, लेकिन अब यह संभव हुआ है। इससे पहले चार बार यह बिल संसद में लाया गया, लेकिन कभी पारित नहीं हुआ। इसे आम सहमति के नाम पर लटकाया गया। ऐसे में प्रश्न स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ही प्रयास में कैसे आम सहमति से इस बिल को पारित करा लिया। आखिर पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसकी एकमात्र वजह है— स्थिरता। केंद्र में आज पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार है, जिसकी पहचान है— साहसिक निर्णय लेना और उसे लागू करवाना। दोनों सदनों में इसका पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है, तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। यही कारण है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार एक आवश्यकता है। कभी बिल फाड़ दिया जाता था, लेकिन आज सभी ने समर्थन किया, तो उसकी वजह है पिछले 10 वर्षों में महिला एक शक्ति बनकर उभरी हैं।

ताकि सक्षम रहे महिला शक्ति

- कोविड काल में महिलाओं को विशेष सहायता दी गई।
- अप्रैल-जून 2020 के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।
- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 14 करोड़ रिफिल सिलेंडर मुफ्त दिए गए।
- भारत में करीब 1.2 करोड़ स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें 88 फीसदी पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूह हैं। इनमें 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक की गई।
- देश में 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला के तहत रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि पारंपरिक ईंधन-लकड़ी, कोयला आदि से खाना पकाने से भारत में सालाना 5 लाख मौतें होती थी। लेकिन केंद्र सरकार के इस प्रयास से महिलाओं में सांस संबंधी बीमारी के मामलों में 20 फीसदी की कमी आई है।

मातृशक्ति का सम्मान

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करेगा। वर्ष 2047 तक के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होगा। महिला सशक्तीकरण को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा, संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा। यह 140 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत भागीदारी रखने वाली मातृ शक्ति का सच्चे अर्थ में सम्मान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नारी के नेतृत्व में विकास की बात समग्र विश्व के सामने रखी। जी-20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने दुनिया को यह अहसास कराया कि मातृशक्ति, बेटियां न केवल नीतियों में सहभागिता कर सकती हैं, बल्कि नीति-निर्धारण में अपने पद को भी सुरक्षित कर पाने में सक्षम हैं। इसकी वजह है कि वर्तमान केंद्र सरकार के लिए महिला सशक्तीकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक संकल्प है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वेतन के रूप में मिली सारी राशि को गुजरात सचिवालय के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई के लिए दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें जितनी भेंट मिली थी, उसकी नीलामी से मिलने वाली राशि भी बच्चियों की पढ़ाई के लिए दान दी थी। कल्पना कीजिए कि आप 140 करोड़ देशवासियों के चुने नेता हैं, जिनके सोशल मीडिया पर बड़े प्रशंसक समूह हैं और प्रधानमंत्री मोदीजी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से 7 महिलाओं को पूरे दिन के लिए सौंप दिया था। कैसी अनुभूति होगी आपको। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना ट्विटर अकाउंट 7 महिलाओं को सौंप दिया था। कथनी और करनी में साम्यता का यह अद्भुत उदाहरण ही दरअसल नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति को समान अधिकार और अवसर दे रहा है, जहां महिलाएं भी सुरक्षा और सम्मान के साथ सशक्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2014 के बाद से तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। भारत में लगभग 43 प्रतिशत एसटीईएम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्नातक महिलाएं हैं। भारत में लगभग एक-चौथाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक महिलाएं हैं। चंद्रयान, गगनयान और मिशन मंगल जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता के पीछे महिला वैज्ञानिकों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत है। आज भारत में उच्च शिक्षा में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक संख्या में प्रवेश ले रही हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महिला पायलटों के मामले में उच्चतम प्रतिशत वाले देश में शामिल हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना में महिला पायलट अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। सभी सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को ऑपरेशनल भूमिकाओं और लड़ाकू मोर्चो पर तैनात किया जा रहा है।

संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ, हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तीकरण के युग की शुरुआत करते हैं। यह महज एक कानून नहीं है; यह उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। एक बार पुनः मे इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ■

(लेखक भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

प्रधानमंत्री ने 'सिंधिया स्कूल' के 125वें संस्थापक दिवस समारोह को किया संबोधित

आपका सपना ही मेरा संकल्प है: नरेन्द्र मोदी

भारत आज जो कुछ भी कर रहा है, वह बड़े पैमाने पर कर रहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 'द सिंधिया स्कूल' के 125वें संस्थापक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने स्कूल में 'बहुउद्देशीय खेल परिसर' की आधारशिला रखी और विशिष्ट पूर्व विद्यार्थियों एवं शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को स्कूल के वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित विशिष्ट प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इस दौरान उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी को बधाई दी। उन्होंने 'आजाद हिंद सरकार' के स्थापना दिवस पर भी देशवासियों को बधाई दी। श्री मोदी ने सिंधिया स्कूल और ग्वालियर शहर के प्रतिष्ठित इतिहास के उत्सव का हिस्सा बनने का अवसर मिलने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने ऋषि ग्वालिपा, महान संगीतज्ञ तानसेन, राजमाता विजया राजे, अटल बिहारी वाजपेयी और उस्ताद अमजद अली खान का उल्लेख किया और कहा कि ग्वालियर की धरती पर हमेशा ही ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। श्री मोदी ने कहा, 'यह नारी शक्ति और वीरता की भूमि है।'

प्रधानमंत्री ने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद तत्काल परिणामों के लिए काम करने या दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने के दो विकल्पों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि सरकार ने 2, 5, 8, 10, 15 और 20 वर्ष से लेकर विभिन्न समय बैंड के साथ काम करने का निर्णय लिया और अब जब सरकार 10 वर्ष पूरे करने के करीब है, तो दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ कई लंबित निर्णय लिए गए हैं।

वर्तमान सरकार युवा पीढ़ी के लिए ऐसा सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, जहां अवसरों की कोई कमी न हो

श्री मोदी ने विभिन्न उपलब्धियां गिनाईं और जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने की छह दशक पुरानी मांग, सेना के पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन देने की चार दशक पुरानी मांग, जीएसटी एवं तीन तलाक कानून की चार दशक पुरानी मांग का उल्लेख किया। उन्होंने हाल ही में संसद में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि वर्तमान सरकार युवा पीढ़ी के लिए ऐसा सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, जहां अवसरों की कोई कमी न हो। यदि यह सरकार नहीं होती, तो अगली पीढ़ी के हित में इन लंबित निर्णयों को आगे न बढ़ाया गया होता।

युवाओं और उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा

प्रधानमंत्री ने कहा, "मुझे युवाओं और उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है।" उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये युवा राष्ट्र द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करेंगे। श्री मोदी ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि फिनटेक को अपनाने की दर, रीयल-टाइम डिजिटल लेनदेन और स्मार्टफोन डेटा उपयोग में भारत पहले स्थान पर है। श्री मोदी ने बताया कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या और मोबाइल विनिर्माण के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है।

उन्होंने तेजस और आईएनएस विक्रांत का भी जिक्र किया और कहा, "भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।"

श्री मोदी ने कहा कि भारत आज जो कुछ भी कर रहा है, वह बड़े पैमाने पर कर रहा है।" उन्होंने विद्यार्थियों से अपने सपनों और संकल्पों के बारे में बड़ा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा "आपका सपना मेरा संकल्प है" और विद्यार्थियों को नमो ऐप के माध्यम से उनके साथ अपने विचार साझा करने या व्हाट्सएप पर उनसे जुड़ने का सुझाव दिया। ■

'इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेसः मन की बात @100'

अब ऑनलाइन उपलब्ध है

वर्ष 2014 में विजयादशमी पर आरंभ हुआ लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की यात्रा के 100 एपिसोड के महत्वपूर्ण पड़ाव की उपलब्धि पर एक पुस्तक संकलित की गयी है। पुस्तक, 'इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेसः मन की बात @100' इस प्रेरणादायक यात्रा को श्रद्धांजलि है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखित एक विशेष प्रस्तावना शामिल है। अब यह पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है। यह पुस्तक केवल लेखों का संग्रह या अतीत का प्रतिबिंब मात्र नहीं है, इसके बजाय यह भारत की प्रगति की कहानी का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।

'इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेसः मन की बात @100' पुस्तक एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और एक व्यापक,और सिलसिलेवार विश्लेषण प्रदान करती है जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों का एक विस्तृत विश्लेषण शामिल है। पुस्तक का पहला खंड प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उनके राष्ट्र के बीच प्रभावी दोतरफा संवाद स्थापित करने के लिए अपनाए गए अनूठे प्रयासों पर प्रकाश डालता है। दूसरा खंड इस बात पर प्रकाश डालता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की अपील का देश के नागरिकों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। पुस्तक का तीसरा खंड भारत की सभ्यता की समृद्धि के बारे में है और चौथा और अंतिम खंड लोकप्रिय रेडियो शो से संबंधित सांख्यिकीय डाटा प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, यह खंड श्रोताओं और एपिसोड की सामग्री का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है, जो आकर्षक परिणामों को उजागर करता है।

मुझे खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने 'मन की बात' पर व्यापक शोध किया है और अपने व्यावहारिक निष्कर्षों को लोगों के साथ साझा किया है। ऐसा ही एक और प्रयास ब्लू क्राफ्ट की पुस्तक 'इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस' है, जो बताती है कि कैसे यह कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बन गया है। इस कार्य के लिए उन्हें बधाई।

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

'इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेसः मन की बात @100' न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अद्वितीय दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। पुस्तक दर्शाती है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण से लेकर टेक्नोजॉकिल इनोवेशन, सांस्कृतिक संरक्षण से लेकर सामाजिक कल्याण तक इसने विचारशील चर्चा और शोध को आगे बढ़ाया है, जिससे देश की प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा मिला है। यह सब

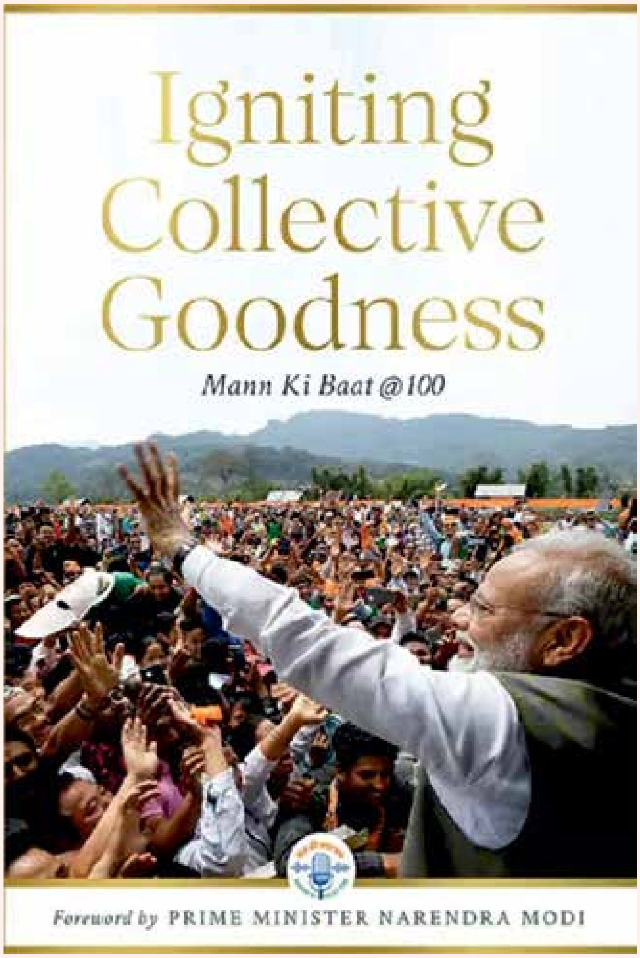

100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात को 'गुणों की पूजा' के रूप में संदर्भित करने के उचित संदर्भ पर आधारित है।

'मन की बात' के बारे में

रेडियो शो 'मन की बात' कई मायनों में एक अभिनव और साहसिक प्रयोग है। कार्यक्रम ने पारंपरिक राजनीतिक और सरकारी परिचर्चाओं से अलग, स्वयं को राष्ट्र के साथ एक विशिष्ट संवाद के रूप में स्थापित किया। इसका फोकस लगातार सामान्य व्यक्तियों के जीवन और उनकी कहानियों पर रहा है, जिन्होंने समाज में असाधारण परिवर्तन लाया है। इस कार्यक्रम से भारतीयों को प्रेरणा मिलती है कि वे अपने आसपास की दुनिया में बदलाव ला सकें। गांव हों या शहर, इस कार्यक्रम से लोगों को अपने समाज में अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। ■

प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की

2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजेगा भारत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 अक्टूबर को भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और अंतरिक्ष अन्वेषण के भारत के प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

अंतरिक्ष विभाग ने ह्यूमन-रेटेड लॉन्च व्हीकल और सिस्टम क्वालिफिकेशन जैसी अब तक विकसित की जा चुकी विभिन्न प्रौद्योगिकियों सहित गगनयान मिशन का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया। इस बात पर गौर किया गया कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल (एचएलवीएम3) के 3 अनक्रूड मिशनों सहित लगभग 20 प्रमुख परीक्षणों की योजना बनाई गई है। बैठक में 2025 में मिशन के लॉन्च की पुष्टि करते हुए इसकी

तैयारी का मूल्यांकन किया गया।

हाल के चंद्रयान-3 और आदित्य एल1 मिशन सहित भारत की अंतरिक्ष संबंधी पहलों की सफलता के आधार पर प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि भारत को अब 2035 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

इस विजन को साकार करने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा के अन्वेषण की योजना तैयार करेगा। इसमें चंद्रयान मिशनों की श्रृंखला, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन (एनजीएलवी) का विकास, एक नए लॉन्च पैड का निर्माण, मानव-केंद्रित प्रयोगशालाओं और संबंधित प्रौद्योगिकियों की स्थापना किया जाना शामिल होगा।

प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर सहित अंतर-ग्रहीय मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयां छूने की देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)............................ (2)..............................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.............................. दिनांक :.............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

20 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच चलने वाली रैपिडएक्स ट्रेन 'नमो भारत' को हरी झंडी दिखाते और स्कूली बच्चों एवं रैपिडएक्स ट्रेन के चालक दल के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

यशोभूमि (नई दिल्ली) में 13 अक्टूबर, 2023 को 9वें जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में 12 अक्टूबर, 2023 को पार्वती कुंड पर पूजा और दर्शन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

महाराष्ट्र में 19 अक्टूबर, 2023 को 'प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र' के शुभारंभ पर लोगों को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

17 अक्टूबर, 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 28 अक्टूबर, 2023
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

नमो ऐप में एक महत्वपूर्ण अनुभाग है जो स्थानीय सांसद से जुड़ने में मदद करता है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बताया कि नमो ऐप में एक महत्वपूर्ण अनुभाग है जो स्थानीय संसद सदस्यों से जुड़ने में मदद करता है। श्री मोदी ने कहा कि यह अनुभाग हमारी लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे आपके संबंधित स्थानीय सांसद के साथ संबंध गहरे होंगे, सांसद के साथ जुड़ने की सुविधा मिलेगी और उनके द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने में भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया—

"नमो ऐप में एक बहुत ही दिलचस्प अनुभाग है जो हमारी लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। यह आपके स्थानीय सांसद के साथ आपके जुड़ाव को आसान एवं सुविधानजक बनाएगा और उनके द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने में भी आपकी मदद करेगा। इसके माध्यम से दिलचस्प सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर जीवंत खेल प्रतियोगिताओं तक, सांसदों और उनके विभिन्न आयोजनों तक पहुंच आसान हो जाएगी। nm-4.com/mymp"

छायाकार: अजय कुमार सिंह